रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

रविवार

05 जुलाई -2026

वर्ष 10, अंक 301

पेज 8, मूल्य 2 रुपए

रांची

पति की हत्या करके बाथरूम में दफनाया, फर्श बनवाई

उसी पर नहाती रही, 45 दिन बाद खुलासा; बोली-पीटता था, इसलिए मार डाला

आगरा (एजेंसी)। आगरा में महिला ने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया। ऊपर से फर्श बनवा दी और उसी बाथरूम में रोजाना नहाती रही। 45 दिनों तक पुलिस और घरवालों को गुमराह किया। जांच के दौरान महिला पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही और रोने का नाटक करती रही। महिला के जेठ को उसके व्यवहार से शक हो गया। उसने महिला से कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो वह साथ देगा। इसके बाद महिला ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बाथरूम का फर्श तोड़ा, जहां से केवल कंकाल बरामद हुआ। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था।

इसी वजह से उसने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। मैंने जेठ को फोन कर राजस्थान से बुलाया, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। मैं दोनों बच्चों और सास को घर से करीब 100 मीटर दूर ले गई और वहीं से तीनों को जेठ के साथ भेज दिया। इसके बाद शव को कमरे से खींचकर बाथरूम में ले गई और गड्ढा खोदकर दफना दिया। जेठ को बताया कि पति उससे झगड़ा कर 5 हजार रुपए लेकर चला गया है। फिर खुद भी राजस्थान चली गई। 8 दिन बाद लौटकर आई।

पति की हत्या करके बच्चों-सास को राजस्थान भेजा

राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा (44) सिकंदरा के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी साल 2010 में रूबी से हुई थी। रूबी इटावा की रहने वाली है। उनकी दो बेटियां रिद्धी (13) और सिद्धी (9) हैं। सुरेंद्र के साथ उनकी मां कमला भी रहती थीं। उन्हें आंखों से कम दिखाई देता है। उनके पिता राधेश्याम शर्मा शिक्षक थे। उनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। बड़े भाई अनिल शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र और रूबी के बीच अनबन रहती थी। 18 मई की सुबह 9-10 बजे रूबी का उनके पास फोन आया था। वह कह रही थी कि घर में पुलिस का कोई केस बन गया है, आप मम्मी और दोनों बच्चों को यहां से ले जाओ। मैंने उससे पूरी बात पूछी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बस तीनों को ले जाने के लिए कहा। रूबी ने यह भी कहा कि घर मत आना, मैंने तीनों को पास की दुकान पर बैठा दिया है, वहीं से ले जाना। मैं भरतपुर से आनन-फानन में आगरा पहुंचा और बच्चों और मां को लेकर आगरा आ गया।

संक्षिप्त समाचार

अयोध्या राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित

- आरोपी पाक का नागरिक हाफिज सईद का रिश्तेदार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने शनिवार को 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। इनमें एक आतंकी वो भी है जिसने अयोध्या में राम मंदिर और नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की रेकी की थी। हालांकि ये रेकी कब की गई थी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इस आतंकी की पहचान मोहम्मद मुसादिक के रूप में हुई है। यह हाफिज सईद का रिश्तेदार है। सरकार का कहना है कि

लिस्ट में शामिल सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। सरकार के मुताबिक ये लोग आतंकियों की भर्ती, भारत में घुसपैठ, आतंकी हमलों की साजिश, आतंक के लिए पैसे जुटाने, हथियार पहुंचाने और अन्य मदद करने में शामिल रहे हैं। घोषित 23 आतंकियों में 6 जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं, जबकि 17 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनमें 7 पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) और 10 पाकिस्तान में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से घोषित आतंकियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है।

बाराबंकी में हाईवे पर बनेंगे दो ओवरब्रिज और 2 अंडरपास

लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर 170 करोड़ खर्च करेगी सरकार

लखनऊ (एजेंसी)। अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों में अंकुश व स्थानीय लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) जल्द काम शुरू करने जा रहा है। जिले की सीमा में हाईवे पर दो ओवर ब्रिज और दो अंडर पास बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। सभी

औपचारिकताएं समय से पूरी हो गईं तो अक्टूबर माह से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। जिसका बजट 170 करोड़ बताया जा रहा है। करीब एक वर्ष पहले बनी इस परियोजना में चार ऐसे स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां लगातार बढ़ते यातायात और सड़क पार करने के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए स्थायी समाधान की जरूरत महसूस की गई थी। योजना के तहत सफेदाबाद और सफदरगंज चौराहा पर ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जबकि सफदरगंज के दादरा और रामसनेहीघाट के भटरिया में अंडर पास का निर्माण होगा।

आपातकालीन सेवाओं में मिलेगा लाभ-इन स्थानों पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और किसानों का प्रतिदिन आवागमन रहते हैं। लोगों को हाईवे पार करने के लिए तेज रफ्तार वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार अवैध कट भी बना लिए जाते हैं। जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

रामगढ़ में अपराधियों पर 24X7 नजर, एसपी ने बनाया 'डिजिटल चक्रव्यूह' और 36 सदस्यीय विशेष टीम का गठन

दैनिक अलग पहचान, अन्नपूर्णा गुप्ता, मुख्य संपादक, नई दिल्ली/

रामगढ़ पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण और मामलों की शीघ्र छानबीन के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग शुरू किया है। इसके लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है तथा 36 सदस्यों वाली ÒCrime Prevention & Detection WingÓ - C.P. & D.W. का गठन किया गया है। यह टीम सीधे पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करेगी और प्रत्येक 15 दिन में इसकी समीक्षा होगी।

1971 अपराधियों का तैयार हुआ डेटाबेस -पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2026 तक के अपराधों का पूरा ब्यौरा एकत्र किया है। इस अवधि में आर्म्स एक्ट, हत्या, रंगदारी, लूट, चोरी, अवैध शराब सहित विभिन्न मामलों में जिन 1971 अपराधियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हुए हैं, उनकी सूची और पुस्तिका बनाई गई है। इसी आधार पर अब इन अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।

दोहरी जांच और डिजिटल प्रोफाइलिंग -पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं कि सूचीबद्ध सभी अपराधियों का भौतिक सत्यापन दो स्तर पर किया जाएगा। पहला सत्यापन संबंधित थाने द्वारा किया जाएगा जहां मामला दर्ज है, और दूसरा सत्यापन उस थाने द्वारा होगा जहां अपराधी वर्तमान में निवास कर रहा है। सत्यापन के बाद प्रत्येक अपराधी की डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर नए पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसमें अपराधी का पूर्व आपराधिक इतिहास, कार्यशैली, वर्तमान

पता और जांच से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी।जमानत पर छूटे अपराधियों पर भी निगरानी यह डिजिटल पोर्टल भविष्य में होने वाले अपराधों के उद्भेदन, सक्रिय अपराधियों की पहचान और विभिन्न थानों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। जिले के सभी थाने इस पोर्टल का उपयोग अनुसंधान और अपराध विश्लेषण के लिए कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जेल से जमानत पर रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों पर भी लगातार निगरानी रखी जा सकेगी।कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को अपराधियों की सूची की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार सीसीए लगाने, जमानत रद्द कराने, पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने और गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने जैसे सख्त कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

रामगढ़ जिले का अपराध आंकड़ा - 01.01.2021 से 31.03.2026 तक

क्र.सं.	अपराध का प्रकार	रामगढ़ जिला	अन्य जिला	राज्य के बाहर	कुल
1	आर्म्स एक्ट	194	119	25	338
2	एनडीपीएस एक्ट	51	17	15	83
3	हत्या	138	10	05	153
4	रंगदारी	50	39	08	97
5	डकैती	23	22	02	47
6	लूट	22	24	02	48
7	छिनतई	14	14	06	34
8	चोरी	282	53	08	343
9	गृहभेदन	91	13	05	109
10	वाहन चोरी	101	99	39	239
11	उत्पाद अधिनियम	153	26	17	196
12	अन्य	255	22	07	284
कुल		1374	458	139	1971

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने आवास पर भरा इन्यूमरेशन फॉर्म

बीएलओ द्वारा सीमित समय में पूरे मतदान केंद्र क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर जाकर सेवा प्रदान करना है

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर एवं हस्ताक्षर कर 64 -हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अपने मतदान केंद्र संख्या 374 कि बीएलओ श्रीमती अन्नु कच्छप को जमा किया। पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि बीएलओ जब आपके घर आयें तो यथा-संभव हाथों हाथ अपना तथा अपने

परिवार का इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर/भवरवाकर एवं हस्ताक्षर कर/कराकर अपने बीएलओ को अवश्य जमा करें। बीएलओ द्वारा सीमित समय में पूरे मतदान केंद्र क्षेत्र के सभी घरों तक जाकर सेवा प्रदान करना है। उन्होंने सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने सुविधानुसार जल्द से जल्द अपने बीएलओ से संपर्क करते हुए अपना तथा अपने परिजनों का इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें एवं भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य 'एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटेगा नहीं एवं एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ेगा नहीं' को प्राप्त करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आवास पर 64 हटिया विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ सुदीप्त राज, बीएलओ सुपरवाईजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर भी उपस्थित थे।

अब बासमती की जंग में भारत से हारा पाकिस्तान

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) की वाणिज्य समिति की बैठक में वाणिज्य सचिव जवाद पॉल ने कहा है कि भारत के सस्ते और आक्रामक चावल निर्यात की वजह से पाकिस्तान का चावल उद्योग पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय विवादों के कारण पाकिस्तान को कुल 3.1 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। शुक्रवार को नेशनल असेंबली की कॉमर्स पर बनी स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया है कि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 1.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जबकि मिडिल ईस्ट में संकट जारी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर में अचानक चली गोली, मची अफरा-तफरी

दैनिक अलग पहचान, साजिद, राज्य ब्यूरो चीफ, झारखण्ड /

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पीएसी जवान की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। गोली सड़क पर जाकर लगी, जिसके बाद वहां से उछली गिट्टियां पास में खड़े लोगों को लग गईं। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद कुछ देर के लिए मंदिर परिसर और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया।घटना में निक्की गुप्ता, रामबाबू और विकास यादव घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों मंदिर के पास फूल-माला की दुकान चलाते हैं। गोली सीधे किसी को नहीं लगी, लेकिन सड़क से उछली गिट्टियां उनके हाथ और पैर में लगीं, जिससे उन्हें हल्की चोट आई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए घायलों को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल पहुंचाया।अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि तीनों घायलों की हालत सामान्य है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और सभी खतरे से बाहर हैं। इस खबर के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली।गोली की आवाज सुनते ही मच गई हलचल प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु और आसपास के लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने इधर-उधर भागना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत लोगों को संभाला और स्थिति को शांत कराया। उनकी सतर्कता की वजह से कोई भगदड़ नहीं मची।जिस पीएसी जवान की कार्बाइन से गोली चली, उसे घटना के तुरंत बाद चौक थाने ले जाया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कार्बाइन किस तरह गिरी और आखिर गोली कैसे चल गई। शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालकाशी विश्वनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा ड्यूटी के दौरान हथियार से अचानक गोली चलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा में तैनात जवानों को हथियार संभालने और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

2 हजार तक पहुंच सकती थी घरेलू सिलेंडर की कीमत

- मोदी ने कहा-सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबर गया भारत
- राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन किया

बालोतरा (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए, उसके कारण घरेलू गैस के दाम 2 हजार रुपए तक जा सकते थे। सरकार ने इसको लेकर बेहतर मैनजमेंट किया। इसी का परिणाम है, सिलेंडर 950 रुपए के करीब मिल रहा है। पीएम आज (शनिवार) राजस्थान के दौरे पर रहे। दोपहर करीब 12 बजे वह बालोतरा के पचपदरा पहुंचे। यहां देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी के कंट्रोल रूम को देखा और एक्सपर्ट्स से बात की। इसके बाद रिफाइनरी का उद्घाटन किया। जयपुर मेट्रो के फेज-2 की आधारशिला (वर्चुअल) भी रखी। इससे पहले शनिवार सुबह करीब 10.40 बजे जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए

टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल को देखा।

'युद्ध के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा'- अप्रैल से जून के बीच पेट्रोल-डीजल से ही कंपनियों को 75 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये इतना बड़ा था कि एक नई रिफाइनरी बन जाए। ये घाटा सरकारी खजाने से भरा गया। युद्ध के समय भारत की दूसरे देशों से दोस्ती बहुत काम आई। पहले जहां 25-26 देशों से ईंधन खरीदते थे, वह 40 देशों तक पहुंच गया। युद्ध के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिखा। कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए ठोस काम नहीं किया। भाजपा क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था।

विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी के लिए + सुरक्षा की मांग, धमकी के बाद आतंकवादी प्रिंस खान का घर जमीनदोज कर दिया गया

प्रिंस खान को कुत्ते की मौत मिलेगी, सामने आने की हिम्मत करे : सोनिया मुर्मू

दैनिक अलग पहचान, मुख्य संपादक, नई दिल्ली/

झारखंड के धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन, रंगदारी और माफिया गतिविधियों के विरुद्ध प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया है। शनिवार को धनबाद पुलिस की टीम ने भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोय के नेतृत्व में की गई। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार को सांसद ढुलू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान पर गंभीर आरोप

विधायक अरूप चटर्जी धमकी मामले में लिखित शिकायत सौंपते हुए (तस्वीर)

लगाए हैं। उन्होंने दोनों के खिलाफ निरसा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है।विधायक ने दावा किया कि हाल ही में उनके द्वारा सांसद के अवैध कारोबार और प्रिंस खान से संबंधों की जांच की मांग के बाद उन्हें प्रिंस खान की ओर से धमकी भरा संदेश मिला था।पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रिंस खान को लंबे समय से क्षेत्र का अत्यंत खतरनाक अपराधी माना जाता रहा है। उसकी गतिविधियां धनबाद की शांति और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी

पुलिस द्वारा आतंकवादी प्रिंस खान के घर को जेसीबी से ध्वस्त करते हुए (तस्वीर)

हुई थीं।यह सख्त कार्रवाई निरसा विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी को प्रिंस खान द्वारा दी गई जानलेवा धमकी के तुरंत बाद की गई है। गैंगस्टर ने विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर रंगदारी की मांग करते हुए स्पष्ट धमकी दी थी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो 24 घंटे के अंदर अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरूप चटर्जी ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है और वे धनबाद पहुंचकर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराने वाले हैं।

विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी पर गंभीर खतरा-मार्क्सवादी समन्वय समिति के पूर्व विधायक शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी के पुत्र तथा सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के विधायक अरूप चटर्जी कोयला माफिया, भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ लगातार संघर्षरत रहे हैं। वे अपने पिता शहीद गुरदास चटर्जी और कॉमरेड अरुण कुमार रॉय (रॉय बाबू) की क्रांतिकारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और आम जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं।अरूप चटर्जी के समर्थकों में गहरी चिंता व्याप्त है। साजिद हुसैन ने कहा, 'कॉमरेड अरूप चटर्जी की जिंदगी केवल उनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह हजारों-लाखों मजदूरों, किसानों और आम जनता की आशा और उम्मीद का प्रतीक है।' समर्थकों ने झारखंड सरकार तथा केंद्र सरकार से तुरंत जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की जोरदार मांग की है।राजनीतिक विवाद के बीच माफिया का हस्तक्षेप-यह धमकी धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के साथ चल रहे राजनीतिक मतभेदों के बीच आई है। अरूप चटर्जी ने सांसद पर कोयला चोरी और अवैध गतिविधियों से संबंधित आरोप लगाए थे तथा प्रिंस खान से कथित संबंधों की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

संक्षिप्त समाचार

बरियातू थाना के पीछे ही चेन स्नेचिंग

रांची, एजेंसी। राजधानी में महिलाओं के लिए गले में सोने की चेन पहनकर निकलना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। बेखौफ स्नैचर्स लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और वीआईपी इलाकों से लेकर थानों के आसपास भी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बरियातू थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार सुबह करीब 9 :55 बजे थाने से महज कुछ ही दूरी पर बाइक सवार दो अपराधियों ने सब्जी लेकर घर लौट रही एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पहले दोनों अपराधी पैदल जा रही महिला से आगे निकलते हैं, फिर बाइक मोड़कर वापस आते हैं और झपट्टा मारकर उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। महिला ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों आरोपी तेजी से भाग निकले। थाने से कुछ ही दूरी पर दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

26 जुलाई से सजेगा फुटबॉल का महाकुंभ

रांची, एजेंसी। 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप में पहली बार मेजबान शहर के रूप में शामिल रांची फुटबॉल के बड़े मुकाबलों का गवाह बनने जा रहा है। झारखंड की राजधानी में 26 जुलाई से टूर्नामेंट के मैच शुरू होंगे, जबकि यहां आखिरी मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा।रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम को ग्रुप-सी के सभी मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है। इस ग्रुप में इंडियन सुपर लीग क्लब जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली (एससी दिल्ली), इंडियन एयर फोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी शामिल हैं।रांची में डूरंड कप का पहला मैच 26 जुलाई को जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई, 4 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त को ग्रुप चरण के अन्य मुकाबले आयोजित होंगे। ग्रुप चरण के समाप्त होने के बाद रांची को नॉकआउट चरण का भी एक अहम मुकाबला मिला है। 16 अगस्त को यहां पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, जिससे शहर में डूरंड कप का रोमांच और बढ़ जाएगा।

तेज हवा-बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी

रांची, एजेंसी। मौसम विभाग ने शनिवार यानी 4 जुलाई को राज्य के सभी 24 जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जुलाई से 8 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 जुलाई को लातेहार, पलामू, चतरा और गढ़वा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार यानी 6 जुलाई को झारखंड के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, चतरा और रांची जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मंगलवार यानी 7 जुलाई को खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

रांची समेत झारखंड के चार शहरों में जल्द शुरू होगी प्रीमियम डाक डिलिवरी सेवा

रांची, एजेंसी। डाक विभाग की नई प्रीमियम डिलिवरी सेवा जल्द ही झारखंड के चार प्रमुख शहरों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में शुरू हो सकती है। इसके लिए विभाग ने डाक निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद इन शहरों के लोगों को पार्सल और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तेज, सुरक्षित और समयबद्ध डिलिवरी की सुविधा मिलेगी। विभाग ने इस सेवा की शुरुआत मार्च 2026 में देश के छह प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में की थी, जहां इसके अच्छे परिणाम मिले हैं।विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रीमियम डिलिवरी सेवा पूरी तरह आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी।

वित्तीय अनुशासन में झारखंड देश के टॉप तीन राज्यों में हुआ शामिल

रांची, एजेंसी। वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर झारखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग की ओर से जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के फिसकल हेल्थ इनडेक्स 2026 में झारखंड देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल हुआ है। राज्य को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है। इस श्रेणी में झारखंड के साथ ओडिशा और गोवा भी शामिल हैं। नीति में आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का प्रदर्शन वित्तीय अनुशासन, राजस्व को संग्रह, व्यय प्रबंधन और कर्ज नियंत्रण जैसे प्रमुख मानकों पर बेहतर रहा है। राज्य ने अपने कुल राजस्व में कर संग्रह की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रखी है। वहीं गैर-कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास भी सफल रहे हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) को सकल राज्य से घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के निर्धारित तीन प्रतिशत से नीचे रखा।रिपोर्ट में इसे मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत माना गया है। विकास कार्यों पर खर्च के मामले में भी झारखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

मिलेट मिशन को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए कृषि मंत्री की समीक्षा बैठक,

अलनीनो और राज्य में संभावित सुखाड़ को लेकर चर्चा

रांची, एजेंसी। जून महीने में झारखंड में मानसून में सामान्य से 54% कम बारिश हुई है. अलनीनो के प्रभाव से इस साल सामान्य से काफी कम बारिश होने और राज्य में संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गयी. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को पशुपालन भवन, हटिया (हेसाग) में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. जिसमें कृषि विभाग के सचिव, विशेष सचिव, विभिन्न निदेशालयों के निदेशक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े.

इस बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि संभावित सुखाड़ की स्थिति में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिकारियों की जवाबदेही और संवेदनशीलता ही किसानों की सबसे बड़ी ताकत होगी.

कृषि मंत्री ने मिलेट मिशन को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए सभी जिलों में तीन दिवसीय विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कम पानी में होने वाली फसलों को बढ़ावा मिल सके.

उन्होंने संभावित सुखाड़ की स्थिति में पशुओं में फैलने वाले संभावित रोगों की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। पशुपालकों को जागरूक करने और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

कृषि मंत्री ने उर्वरकों की कालाबाजारी पर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य में गठित टास्क फोर्स द्वारा अब तक 436 छापेमारी की गई है। इस दौरान 11 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने संभावित सुखाड़ को देखते हुए सबसे पहले अपना कंटिन्जेंसी प्लान केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मई माह में ही आकस्मिक कार्ययोजना तैयार कर ली थी और उसी के प्रभावी क्रियान्वयन की बिंदुवार समीक्षा की जा रही है।मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अलनीनो के प्रभाव के कारण देश के कई राज्यों की तरह झारखंड में भी सामान्य से

लगभग 54 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

उन्होंने बताया कि उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पलामू जिला सर्वाधिक प्रभावित है, जबकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के कुछ जिलों में भी वर्षा की कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य के लगभग 20 से 30 प्रतिशत क्षेत्र में ही बिचड़ा तैयार हो पाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दस दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो 15 जुलाई तक बुआई का रकबा बढ़ाकर लगभग 60 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री ने किसानों से मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए मड़ुआ, दलहन एवं तिलहन जैसी कम पानी में होने वाली वैकल्पिक फसलों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई जिलों में किसान इन फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो भविष्य की दृष्टि से सकारात्मक संकेत है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरक समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा, कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखने और संभावित सूखाड़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ ही भूमि संरक्षण प्रभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विभिन्न निर्देश दिए हैं बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सभी योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में निदेशालय द्वारा शीघ्र ही विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (स्ह्क्क) जारी किया जाएगा, जिसका सभी जिलों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्ष के अंतिम महीनों में कार्य प्रारंभ करने तथा व्यय दर्शाने की प्रवृत्ति समाप्त की जाए, क्योंकि इससे अनावश्यक देनदारियां बढ़ती हैं। मौसम अथवा जलभराव जैसी परिस्थितियों को कार्य में विलंब का कारण न बनाते हुए समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केवल माननीय विधायकों की नई अनुशंसाओं के आधार पर ही योजनाओं का चयन किया जाएगा। जिन योजनाओं की अनुशंसा पिछले वर्ष की गई थी, लेकिन जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, उनके लिए संबंधित माननीय विधायक से नए लेटर पैड पर पुनः अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए केवल नई अनुशंसाओं को ही स्वीकार किया जाएगा।

बिरसा पक्का चेक डैम योजना के संबंध में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम-से-कम एक संभावित स्थल का भौतिक सत्यापन कर उसकी रिपोर्ट माह के अंत तक निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, संबंधित माननीय विधायक से भी योजना के लिए अनुशंसा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इस बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि लंबित बिलों के संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं को लेकर पूर्व की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया है।

गढ़वा में जेएमएम के अंदर बगावत, भवनाथपुर विधायक के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा

गढ़वा, एजेंसी। जिले में जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव के खिलाफ उनके मजबूत साथी रहे भोजपुर गढ़ के युवराज ने मोर्चा खोल दिया है। सैंकड़ों कार्यकताओं के साथ जेएमएम नेता दीपक प्रताप देव ने अपने आवास पर प्रेसवार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक को विकास से मतलब नहीं है। विधायक सिर्फ अपने हित में ज्यादा बात करते हैं।

भाजपा के कद्दावर नेता भानु प्रताप शाही को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हराना चुनौती से कम नहीं था। जेएमएम पार्टी से अनंत प्रताप देव को टिकट मिलने के बाद पार्टी ने तीन नेताओं को एक किया था। जिसमें वर्तमान विधायक अन्नत प्रताप देव, ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव शामिल था। दीपक प्रताप देव ने चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के लिए खूब प्रचार किया था। वह राज परिवार के होने के वजह से उनके समर्थक भी हजारों में हैं और उनके समर्थन के कारण समर्थकों ने अनंत प्रताप देव को अपना समर्थन दिया था।

यही वजह है कि पिछले चुनाव में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही को हराकर अनंत प्रताप देव जीत दर्ज की थी। चुनाव के डेढ़ वर्ष बीतते ही जेएमएम नेता दीपक प्रताप देव ने वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 2029 का

विधानसभा चुनाव खुद से लड़ने का ऐलान कर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचल को अभी से ही बढ़ा दी है।

दीपक प्रताप देव ने कहा कि अनंत प्रताप देव हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मामले में हम अब उनसे दुरी बना लिए है। क्योंकि जब से वे विधायक बने हैं, तब से हमारे समर्थकों का अनदेखी कर रहे हैं। वे किसी के काम पर उड़ते है, हमने बहुत मेहनत कर उनको जिताया था। लेकिन अब वे पहले वाले नहीं रहे बल्कि अब विधायक जी हो गए है। दीपक देव ने कहा की जब से चुनाव हुआ है। जीत के बाद ही ये पूर्ण रूप से विधायक बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक अपने क्षेत्र में विधायक ने विकास का कोई कार्य नहीं किए हैं, एक समय वे कांग्रेस के टिकट लेकर एयरपोर्ट पर ही फेक दिए थे और भाजपा का दामन थाम लिए थे।

24 जिलों के सभी थानों से जुड़ा 'मिशन वात्सल्य पोर्टल'

अब देशव्यापी नेटवर्क से 6 माह में रांची से लापता हुए 42 बच्चों की खोज होगी आसान

रांची, एजेंसी। रांची समेत झारखंड में लापता हुए बच्चों की सुरक्षित घर वापसी के लिए पुलिस ने अब अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। सीआईडी की अगुवाई में झारखंड के सभी 24 जिलों के थानों को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 'मिशन वात्सल्य पोर्टल' से जोड़ दिया गया है।इस हाईटेक व्यवस्था के तहत झारखंड पुलिस अब राष्ट्रीय स्तर के लापता और बरामद बच्चों के डेटाबेस से सीधे जुड़ गई है। इस देशव्यापी नेटवर्क के जरिए पुलिस अत्याधुनिक डिजिटल तरीके से बच्चों को ट्रैक कर सकेगी, जिससे उनकी पहचान और बरामदगी की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य पोर्टल पर लापता और बरामद बच्चों का राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस उपलब्ध है।

थानों के सीसीटीएनएस ऑपरेटर करेंगे मिलान अब सभी थानों के सीसीटीएनएस ऑपरेटर किसी भी बरामद या अज्ञात बच्चे

के हुलिए और विवरण का मिलान इस पोर्टल पर उपलब्ध राष्ट्रीय रिकॉर्ड से करेंगे। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 'खोया-पाया' और 'ट्रैक चाइल्ड' जैसी प्रणाली समाहित है। इस देशव्यापी नेटवर्क से जुड़ने के बाद अब पुलिस अत्याधुनिक तरीके से बच्चों को ट्रैक कर सकेगी, जिससे लापता बच्चों की बरामदगी की प्रक्रिया आसान होगी।

गेम चेंजर साबित होगा मिशन वात्सल्य, मानव तस्करी पर लगेगी रोक मिशन वात्सल्य पोर्टल झारखंड पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लापता बच्चों की तलाश में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पोर्टल विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया को तेज करेगा, जिससे बच्चों की जल्द पहचान और सुरक्षित बरामदगी की संभावना बढ़ेगी। इससे पुलिस की कार्यक्षमता सुधरेगी व मानव तस्करी रुकेगी।- डॉ आनंद ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर

रांची विश्वविद्यालय : राज्य में 6 साल में 3025 बच्चे हुए लापता सरकारी आंकड़े के अनुसार झारखंड में वर्ष 2020 से 2025 के बीच यानी छह वर्षों में 3025 बच्चे लापता हुए। इनमें से 2788 बच्चों को बरामद कर लिया गया, जबकि 237 बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वर्ष 2025 में बच्चों के लापता होने के 717 मामले दर्ज हुए। वहीं रांची से जनवरी से जून तक 42 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 34 को बरामद कर लिया गया है।

कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू,

बड़े संस्थानों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन !

रांची, एजेंसी। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, स्त्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण तथा सभी पात्र संस्थानों का एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना था।

इस बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए अपने परिसर में चार रंगों के डस्टबिन हरा, नीला, लाल और काला रखना तथा स्त्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण करना अनिवार्य कर दिया

गया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्ड्ड्रू पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नियमों के अनुसार जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है। ऐसे ही अगर प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है।

इस बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और नियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और वैज्ञानिक बनेगी।

अपर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में उत्पन्न गीले एवं बागवानी अपशिष्ट का स्वयं प्रसंस्करण सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अधिकृत एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित एजेंसी निर्धारित मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण कर रही है।

इस बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत प्रदर्शन भी किया। जिससे सभी संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर बिना किसी परेशानी के अपना पंजीकरण पूरा कर सकें।

पलामू के तरहसी थाना प्रभारी निलंबित, पैसे के लेनदेन के आरोप में एसपी ने की कार्रवाई

पलामू, एजेंसी। जिला के तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम को निलंबित कर दिया गया है। पलामू एसपी कपिल चौधरी ने थाना प्रभारी आनंद राम को निलंबित किया है। आनंद राम 2018 बैच के सब-इंस्पेक्टर हैं। आनंद राम पलामू के पाटन समेत कई थानों में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहे हैं। करीब एक वर्ष पहले सब इंस्पेक्टर आनंद राम तरहसी थाना प्रभारी के पद पर तैनात हुए थे। निलंबित होने के बाद सब इंस्पेक्टर आनंद राम को पुलिस लाइन भेजा गया है।

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पैसे के लेन-देन के आरोप के निलंबित किया गया है। इस मामले के आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल, तरहसी के रहने वाले एक कारोबारी ने पलामू एसपी से पैसे के लेन-देन को लेकर शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की

गयी, जांच के बाद थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है।

तरहसी के इलाके में पुलिस ने मई महीने कुछ गाड़ियों को पकड़ा था। आरोप है कि पकड़े गए गाड़ियों को छोड़ने के एवज में लेनदेन हुई है और कारोबारी को परेशान किया गया है। पलामू का तरहसी थाना लेस्लीगंज पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत आता है। यह इलाका मनातू पिपराटांड़ पाटन पांकी और लेस्लीगंज थाना से सटा हुआ है।

तरहसी का इलाका अफीम की खेती के लिए भी चर्चित रहा है और नक्सल गतिविधि के लिए भी यह जाना जाता रहा है।

श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाकर श्रद्धालुओं को सहज अनुभव देने का प्रयास किया जाएगा

देवघर में बाबा मंदिर गर्भगृह में मोबाइल पर पूर्ण रोक, सालभर बाह्य अर्घा से जलार्पण की व्यवस्था

देवघर, एजेंसी। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब भक्तों को सालभर बाह्य अर्घा प्रणाली के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन ले जाने और उसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। ये सभी निर्णय श्रावणी मेला-2026 की तैयारियों को लेकर की गई है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने ये निर्णय पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, बाबा मंदिर प्रभारी व एसडीओ रवि कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी, तीर्थ पुरोहित, सरदार पंडा और पंडा धर्मरक्षिणी सभा के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लिए है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बाबा मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित जलार्पण कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में मंदिर परिसर के बाहर स्थायी बाह्य अर्घा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद श्रद्धालु बिना अधिक भीड़-भाड़ के सीधे बाबा को जल अर्पित कर सकेंगे।

खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और अस्वस्थ श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा बेहद राहतकारी साबित होगी। उन्हें अब लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी और वर्षभर आराम से जलार्पण कर सकेंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को शीघ्र धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है।

मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गर्भगृह में मोबाइल फोन के प्रवेश और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का

निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी, सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होगी और दर्शन-पूजन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सकेगी।

प्रबंधन ने भीड़ प्रबंधन, शीघ्र दर्शन की व्यवस्था, वीआईपी पूजा प्रबंधन, नए फुटओवर ब्रिज के निर्माण, क्लॉक रूम की सुविधा और श्रद्धालुओं की अन्य आवश्यकताओं पर भी विस्तार से चर्चा की है। पंडा धर्मरक्षिणी सभा के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे, जिस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाकर श्रद्धालुओं को सहज अनुभव देने का प्रयास किया जाएगा।

इधर, 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास और बाबा बैद्यनाथ धाम में लगने वाले श्रावणी मेले को लेकर रेलवे में बुकिंग अभी से चालू है। रांची से जसीडीह और देवघर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में करीब 80 प्रतिशत सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं, जबकि कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में 30 जुलाई से 4 अगस्त तक सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर में वेटिंग चल रही है। 15027 मौर्या एक्सप्रेस में 30 जुलाई से 13 अगस्त तक स्लीपर में 40 से 55 सीटें शेष हैं, जबकि अन्य श्रेणियों में सीमित सीटें बची हैं।

18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस में 30 जुलाई से 15 अगस्त तक एसी कोचों में 25 से 80 सीटें उपलब्ध हैं, वहीं स्लीपर में भी कम सीटें बची हैं। 18619 इंटरसिटी एक्सप्रेस में 28 जुलाई से 13 अगस्त तक एसी कोचों में 5 से 32 सीटें ही उपलब्ध हैं। 17007 चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस में भी कई तारीखों पर वेटिंग शुरू हो गई है।

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रांची रेल मंडल ने रांची से भागलपुर तक मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा है। जिसके तहत यह ट्रेन सप्ताह में चार दिन कुल 29 ट्रिप कर सकती है और 24-25 जुलाई से इसके संचालन की संभावना जताई जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

देवघर में बलथर की मुखिया सुनीता देवी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी

देवघर, एजेंसी। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड की बलथर पंचायत की मुखिया सुनीता देवी के ठिकानों पर शनिवार सुबह से आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की। कार्रवाई सुबह करीब छह बजे शुरू हुई, जो समाचार लिखे जाने तक जारी थी। आयकर विभाग की टीम बलथर गांव स्थित उनके पैतृक आवास के साथ-साथ देवघर शहर के बैजनाथपुर मोहल्ले में स्थित आवास की भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार बलथर स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने मुखिया सुनीता देवी से कई घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई बिहार से जुड़े किसी आयकर मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छापेमारी के दौरान दोनों स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक दर्जन से अधिक आयकर अधिकारी और एसएसबी के जवान जांच में लगे हैं। जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की टीम चार-चार इनोवा वाहनों के काफिले के साथ दोनों ठिकानों पर पहुंची। कार्रवाई की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में दिनभर इस छापेमारी की चर्चा होती रही। आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है।

रांची में डीपीएस चौक से मेकन तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

रांची, एजेंसी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर संचालित दो अवैध गैरेज हटाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि गैरेज संचालकों ने बड़ी संख्या में गाड़ियों को सड़क किनारे पार्क कर रखा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और जाम की समस्या हो रही थी। रांची नगर निगम की टीम ने दोनों गैरेज संचालकों को 24 घंटे के भीतर सभी गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही सड़क किनारे बनाई गई अस्थायी स्ट्रक्चर को भी हटाया गया। अभियान के दौरान लंबे समय से लावारिस हालत में खड़े एक पुराने वाहन को ध्वस्त कर जब्त कर लिया गया। नगर निगम ने बताया कि शहर के अलग-अलग इलाकों में ऐसे अनुपयोगी वाहनों की पहचान की जा रही है, जो यातायात में बाधा बन रहे हैं। निगम ने गाड़ी मालिकों से तत्काल वाहन हटाने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि निर्देश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित कई दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। इन दुकानों में तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा सहित अन्य सामग्री बेची जा रही थी, जिससे क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ जुट रही थी। नगर निगम को स्थानीय लोगों से छेड़छाड़ और असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें भी मिली थीं। चूंकि यह क्षेत्र शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय परिसरों के पास है, इसलिए सभी अवैध दुकानों को हटाया गया। इसके अलावा भुसुर नदी के पास संचालित दो अवैध मीट दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि दुकानों से निकलने वाले मीट के अवशेष नदी और उसके आसपास फेंके जा रहे थे, जिससे प्रदूषण फैलने की आशंका थी।

रांची नगर निगम ने बंद कराया मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 40 वर्षों से लगने वाले साप्ताहिक बाजार को निगम ने शनिवार को बंद करवा दिया। अधिक भीड़ और ट्रैफिक जाम की वजहों से निगम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। निगम के इस निर्णय के बाद सब्जी विक्रेता आंदोलन की तैयारी में है। मोरहाबादी में शनिवार को शहर का सबसे बड़ा सब्जी बाजार लगता है, जिसे इस बार लगाने की इजाजत नहीं दी गई। निगम के आदेश के बाद सब्जी विक्रेताओं को वापस भेज दिया गया। हालांकि अधिकांश सब्जी विक्रेता, जो रांची के बेहद ग्रामीण इलाकों से आते हैं, वह सुबह ही वापस लौट गए। लेकिन 100 से ज्यादा सब्जी विक्रेता अभी भी मोरहाबादी मैदान में जमे हुए हैं और आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। निगम के कर्मचारियो ने बताया कि उन्हें सीनियर अफसरों का निर्देश प्राप्त हुआ था कि अब मोरहाबादी का साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। उसी आदेश के बाद निगम और पुलिस की टीम ने सब्जी विक्रेताओं को यहां सब्जी लगाने नहीं दिया गया। निगम की कई टीमें मोरहाबादी मैदान में तैनात की गई है। बता दें कि पिछले 40 सालों से ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों सब्जी विक्रेता रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी ताजा सब्जियां बेचा करते हैं। पहले बुधवार और शनिवार को सब्जी विक्रेता रांची पहुंचते हैं और फिर देर रात अपने-अपने घरों को लौट जाते हैं। सब्जी बाजार हटाने के निर्णय के बाद विक्रेताओं में खाशा आक्रोश है। रातू के रहने वाले राम महतो ने बताया कि वे पिछले 35 सालों से मोरहाबादी मैदान में सब्जियां बेचकर अपने परिवार चला रहे हैं। फल विक्रेता मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि वह भी लगभग 25 सालों से मोरहाबादी मैदान में फल बेचा करते हैं।

ग्रीन पैच विकास को मिलेगी रफ्तार, 630 जमीनों का म्यूटेशन!

रांची नगर निगम का बड़ा अभियान

रांची, एजेंसी। शहर को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा एवं हॉर्टिकल्चर शाखा के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में बताया गया कि नगर निगम की 630 भूमि के म्यूटेशन के लिए संबंधित अंचलों में आवेदन किए जा चुके हैं। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का नियमित फॉलो-अप कर जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निगम की भूमि का समय पर म्यूटेशन अतिक्रमण रोकने, सरकारी संपत्तियों के संरक्षण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है।

इस बैठक में शहर के 24 प्रमुख स्थानों पर ग्रीन पैच विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की गई। करमटोली चौक, मोरहाबादी, जवाहर नगर, खेलगांव, कांके रोड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर हरित क्षेत्र विकसित कर शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर आयुक्त ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

इसके बाद सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने डीपीएस चौक से मेकॉन तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क, फुटपाथ, नदी किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान दो अवैध गैरेज, कई अस्थायी दुकानें और दो अवैध मीट शॉप हटाई गईं। साथ ही लंबे समय से सड़क किनारे खड़े एक लावारिस कबाड़ वाहन को भी जब्त किया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि गैरेज संचालकों ने बड़ी संख्या में वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर रखा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। नगर निगम ने दोनों संचालकों को 24 घंटे के भीतर वाहन हटाने का निर्देश दिया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं तंबाकू, सिगरेट, पान और गुटखा बेचने वाली अवैध दुकानों को भी हटाया गया, क्योंकि वे शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों के समीप संचालित हो रही थीं।

भुसूर नदी किनारे संचालित दो अवैध मीट दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि दुकानों से निकलने वाला मीट का अवशेष नदी और आसपास फेंका जा रहा था। जिससे प्रदूषण फैल रहा था और बड़ी संख्या में पक्षियों का जमावड़ा लग रहा था। इसे पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मानते हुए दोनों दुकानों को तत्काल हटवा दिया गया। साथ ही भुसूर नदी किनारे और अन्य उपयुक्त स्थानों पर ग्रीन पैच विकसित कर सौंदर्यीकरण का भी निर्देश दिया गया।

सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। सड़क, फुटपाथ, नदी-नालों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ नगर निगम की भूमि का संरक्षण और शहर में हरित क्षेत्रों का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करें, ताकि रांची को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और हरित शहर बनाया जा सके।

नगर निगम ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़क, फुटपाथ, नदी-नालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें तथा बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यवसाय संचालित न करें। निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान और शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य आगे भी लगातार जारी रहेगा।

पंचायतों को 16वें वित्त आयोग से मिलेंगे 14231 करोड़ रुपये, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

रांची, एजेंसी। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली अनुदानित राशि को लेकर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं। इसमें झारखंड की पंचायतों को 2026-27 से 2030-31 के बीच 14,231 करोड़ देने का आश्वासन दिया गया। इसमें 11,385 करोड़ बेसिक ग्रांट और 2,846 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट मिलना है।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने 16 वें वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदानित राशि को समय पर देने और परफॉर्मेंस ग्रांट में उदारता दिखाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि समय पर अनुदान राशि नहीं मिलने से पंचायतों की विकास योजनाओं पर असर पड़ता है। मंत्री ने 15 वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को मिलने वाली बकाया राशि के भुगतान की मांग को मजबूती से रखा। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहें। झारखंड जैसे राज्यों में पंचायतों की स्वयं के स्रोत से राजस्व संग्रहण क्षमता अभी सीमित है। इसलिए ऐसे मामलों में नरम रूख अपनाने की जरूरत है। वित्त आयोग का उद्देश्य राज्यों और पंचायतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पंचायतों को राजस्व संग्रहण, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त सहयोग दिया जाए।

रामगढ़ पुलिस की डिजिटल पहलः अपराधियों की निगरानी के लिए बना विशेष मॉनिटरिंग पोर्टल

रामगढ़, एजेंसी। पुलिस द्वारा आरोप-पत्रित अपराधियों की डिजिटल प्रोफाइलिंग और निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अपराधियों का आपराधिक इतिहास, वर्तमान स्थिति, सत्यापन विवरण और अपराध की कार्यप्रणाली दर्ज की जाएगी, जिससे भविष्य में मामलों के त्वरित उद्भेदन में मदद मिलेगी।

रामगढ़ पुलिस ने 01 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2026 तक विभिन्न गंभीर मामलों में आरोप-पत्रित कुल 1971 अपराधियों की सूची तैयार की है। इसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, लूट, डकैती, रंगदारी, चोरी, वाहन चोरी सहित अन्य अपराध शामिल हैं।

नवगठित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना एवं ओपी प्रभारी सहित नोडल पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। यह विंग पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष निर्देशन में कार्य करेगा और इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है कि आरोप-पत्रित अपराधियों का दोहरा भौतिक सत्यापन किया जाए। यदि अपराधी किसी अन्य थाना क्षेत्र में रह रहा है, तो दोनों थाना मिलकर सत्यापन करेंगे और उसकी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में तैयार की जाएगी।

इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से जमानत पर रिहा हुए अपराधियों की नियमित निगरानी भी की जाएगी। साथ ही आवश्यकतानुसार डोजियर, निगरानी प्रस्ताव, सीसीए कार्रवाई और जमानत निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।

रामगढ़ पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अपराध या अपराधियों से जुड़ी किसी भी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। रामगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तकनीक और सख्ती दोनों स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

मिलेट मिशन को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए

कुलपतियों के अधिकारों में कटौती, अब चपरासी की नियुक्ति भी नहीं कर पाएंगे

रांची, एजेंसी। झारखंड के विश्वविद्यालयों में अब नियुक्ति, खरीद, टेंडर और आउटसोर्सिंग की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है। इसके लिए कुलपतियों के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। अब कुलपति चपरासी तक की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे। जबकि अभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती का अधिकार था। वहीं अलग-अलग विश्वविद्यालयों में अपने-अपने तरीके से खरीद और संविदा पर बहाली होती थी, लेकिन अब एक समान नियमों के तहत यह काम होगा।

दरअसल राज्य सरकार ने स्टैच्यूट्स फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड-2026 का मसौदा तैयार किया है। इसमें पहली बार विश्वविद्यालयों के लिए अलग प्रोक्योरमेंट मैनुअल और मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल बनाया गया है। इसके लागू होने के बाद बिना निर्धारित प्रक्रिया के कोई सामान नहीं खरीदा जा सकेगा और न ही किसी एजेंसी को सीधे आउटसोर्सिंग का काम दिया जा सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य खरीद और बहाली प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना, वित्तीय अनियमितता को रोकना और सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसी व्यवस्था लागू करना है।

अभी कुलपति के पास क्या अधिकार हैं तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी नियुक्ति कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी मुख्यालय व अंगीभूत कॉलेजों में अनुबंध पर नियुक्ति कर सकते हैं। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित फैसला लेने का अधिकार है जैप आईटी से सूचीबद्ध न होने पर भी एजेंसियों को आउटसोर्सिंग का काम आवंटित कर सकते हैं। आंतरिक संसाधनों से भवन निर्माण, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने और खर्च का अधिकार है। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति देने का अधिकार है।

कर्मचारियों की बहाली के लिए मैनपावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल बनेगा सामान खरीदने के लिए अलग प्रोक्योरमेंट मैनुअल बनेगा। कर्मचारियों की बहाली के लिए मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल बनेगा। सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी डेटा एंट्री ऑपरेटर और तकनीकी कर्मचारी समेत किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसियों का चयन केवल आउटसोर्सिंग आईटी या राज्य सरकार के अधिकृत ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से होगा।

सरसों तेल में मिला था जहरीला आर्गेमोन

इसी के खाने से पलामू में एक ही परिवार के पांच लोगों की हुई मौत

पलामू, एजेंसी। पलामू के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की जांच और रांची के नामकुम स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार घर से लिए गए सरसों के तेल के नमूने में जहरीले आर्गेमोन (कटेली) के तेल की मिलावट पाई गई है। प्रारंभिक जांच के आधार पर इसी वजह से परिवार के सदस्यों की मौत होने का संदेह जताया गया है।

क्या बता रही है जांच रिपोर्ट : जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में गंभीर एनीमिया (हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम), एक्यूट किडनी इंजरी (किडनी को गंभीर नुकसान) तथा खून की उल्टी और दस्त जैसे लक्षण मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये सभी लक्षण आर्गेमोन विषाक्तता से मेल खाते हैं। लगातार मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 22 से 30 जून के बीच गांव में सर्वे किया। जांच में पता चला कि मृतक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। अपने खेत में उगाई गई सरसों से घर पर ही तेल निकलवाकर इस्तेमाल करता था। उसी खेत में बड़ी मात्रा में आर्गेमोन मेक्सिकाना (कटेली) नामक जहरीला खरपतवार भी उगा हुआ था।

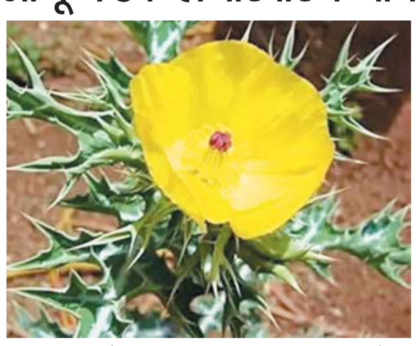

आशंका है कि कटाई या तेल निकालने के दौरान कटेली के बीज सरसों में मिल गए, जिससे तेल जहरीला हो गया। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने 2 जुलाई को जांचे गए सरसों के तेल के नमूने में आर्गेमोन तेल की मौजूदगी की पुष्टि की है। रिपोर्ट में इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं मानते हुए असुरक्षित खाद्य पदार्थ घोषित किया गया है। अन्य रासायनिक जांच की अंतिम रिपोर्ट और मृतकों के विसरा परीक्षण की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

रिम्स में भर्ती सुनील बोले- मैंने वह सरसों तेल नहीं खाया : सिक्का गांव के इस परिवार की छठी सदस्य लाखो देवी और सातवें सदस्य सुनील मेहता का रिम्स में इलाज चल रहा है। रिम्स में भर्ती सुनील मेहता ने बताया कि जब वह कमाने के लिए घर से बाहर गए थे, तब तक घर में सरसों का तेल नहीं पेरवाया गया था। उन्होंने दावा किया कि जिस सरसों के तेल का अब नमूना लिया गया है, उसका उन्होंने सेवन नहीं किया था। हालांकि वह भी पिछले एक सप्ताह से बीमार हैं। उनमें भी परिवार के अन्य सदस्यों जैसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर प्रभावित गांव में घर पर निकाले गए सरसों के तेल की बिक्री और उसके सेवन पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की है। साथ ही पूरे गांव के लोगों की सामूहिक स्वास्थ्य जांच कराने की भी अनुशंसा की गई है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति में आर्गेमोन विषाक्तता के लक्षण मिलने पर समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। विभाग ने स्थानीय प्रशासन को दूषित तेल के इस्तेमाल से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की सलाह दी है। इसके अलावा कृषि विभाग को सरसों की फसलों में उगने वाले कटेली जैसे जहरीले खरपतवार को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने की सिफारिश की गई है।

जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज अफसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 743 अभ्यर्थी हुए सफल

रांची, एजेंसी। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 170 पदों के लिए फॉरेस्ट रेंज अफसर (वन क्षेत्र पदाधिकारी) के लिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसमें 743 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। चयनित अभ्यर्थी को अब 22, 23, 24 व 25 जुलाई 2026 को शारीरिक परीक्षण में शामिल होना होगा। इसके लिए जगह और तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

जुलाई 2024 से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का आयोजन 29 जून 2025 को लिया गया था। जिसमें लगभग 14 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। बायोमैट्रिक उपस्थिति को लेकर कई केंद्र में अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था। इसके बाद आयोग ने तीन जुलाई 2025 को मॉडल उत्तर जारी किया गया था। इसके बाद संशोधित मॉडल उत्तर 26 अगस्त, 10 अक्तूबर, 13 अक्तूबर व 11 नवंबर 2025 को जारी किया गया।

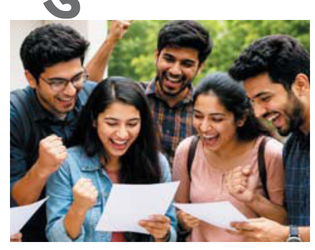

पांच दिसंबर 2025 को पीटी का रिजल्ट जारी किया गया। जिसमें 2405 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए। आयोग द्वारा 22 व 24 जनवरी 2026 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। मुख्य परीक्षा के बाद तीन जुलाई 2026 को रिजल्ट जारी किया गया। मुख्य परीक्षा 550 अंकों की ली गयी थी। इंटरव्यू 50 अंकों का होगा।

फॉरेस्ट रेंज अफसर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षण में पुरूष की ऊंचाई एसटी के लिए 152.5 सेमी और अन्य कोटि के लिए 163 सेमी जरूरी है। वहीं एसटी महिला के लिए 145 सेमी और अन्य कोटि के लिए 150 सेमी होनी चाहिए।

गुमला में बस यात्रियों को राहत, तय हुआ किराया, मनमानी वसूली पर होगी कार्रवाई

गुमला, एजेंसी। बैठक में एसडीपीओ, नप इओ, थाना प्रभारी सहित बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं बस संचालक उपस्थित रहे। एसडीओ ने बताया कि गुमला अनुमंडल क्षेत्र से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि अलग-अलग मार्गों पर निर्धारित दर से अधिक किराया लिया जा रहा है। विशेष रूप से गुमला-रांची मार्ग पर पूर्व में 140-150 रुपये लिया जाता था। लेकिन अब 200 से 230 रुपये तक किराया वसूले जाने की शिकायतें मिल रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस दौरान बस एसोसिएशन द्वारा ईंधन, यूरिया, टोल टैक्स एवं अन्य परिचालन खर्च में वृद्धि का हवाला देते हुए किराया संशोधन का पक्ष रखा गया। इसके बाद सर्वसम्मति से अलग-अलग प्रमुख मार्गों के लिए अधिकतम किराया निर्धारित किया गया। गुमला से रांची 180 रुपये, सिमडेगा 140 रुपये, लोहरदगा 90 रुपये, डुमरी 120 रुपये और जशपुर 120 रुपये किराया निर्धारित किया गया। अन्य मार्गों के लिए बस एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत संशोधित किराया सूची (रेट चार्ट) को भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

एसडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने अथवा शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित बस मालिक, बस संचालक एवं एजेंटों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। इन आदेशों के अनुपालन की जवाबदेही बस एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव एवं उनके प्रतिनिधियों की होगी। हर बस डिपो और टिकट काउंटर पर स्वीकृत किराया सूची (रेट चार्ट) स्पष्ट एवं प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए, ताकि यात्रियों को निर्धारित किराये की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। एसडीओ ने नगर परिषद गुमला को भी सभी संबंधित स्थलों पर रेट चार्ट प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बस एसोसिएशन से शहर को जाममुक्त बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा, पारदर्शी किराया व्यवस्था और यातायात सुनिश्चित करना सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला को सौंपा गया। बैठक में शहर को जाम से मुक्त रखने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित बस ठहराव स्थलों का ही उपयोग करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत सिसई रोड स्थित भट्टी तालाब के पास, पालकोट रोड स्थित एसबीआई बैंक के पास, लोहरदगा रोड स्थित कुम्हार ढलान के पास तथा जशपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के पास बसों का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त शहर में कहीं भी बस रोककर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने पर संबंधित बस संचालकों के साथ-साथ बस एसोसिएशन की भी जवाबदेही तय की जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कोई बस अपने निर्धारित बस स्टॉपेज प्वाइंट के बजाय शहर के विभिन्न स्थानों पर रुक-रुक कर सवारी उठाती है तो इसके लिए बस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव उत्तरदायी होंगे।

वित्त विभाग में लटक रही योजनाओं की फाइल, तीन मंत्रियों ने जताई आपत्ति

रांची, एजेंसी। झारखंड के मंत्रियों में वित्त विभाग के खिलाफ नाराजगी है, जो गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में खुलकर सामने आ गई। इस मौके पर नगर विकास और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने वित्त विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। नाराज मंत्रियों का कहना था कि वित्त विभाग में महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, जिससे उनके विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारी जानबूझ कर फाइल लटका कर रखते हैं और अनावश्यक जानकारी मांगते हैं। मंत्रियों का कहना था कि वित्तीय अनुशासन सही है, लेकिन फाइल रोकना सही नहीं है। समय पर पैसे नहीं मिलने से काम प्रभावित हो रहा है।

रिम्स टू निर्माण के लिए कैबिनेट ने 4000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। यह फाइल वित्त विभाग के पास पहुंची थी, तो विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से पूछा कि इतने बड़े अस्पताल के लिए मानव संसाधन को लेकर क्या कार्ययोजना है। इस अस्पताल में दर्जनों विभाग होंगे। इसके लिए बड़े मानव संसाधन की जरूरत होगी। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर, पारा मेडिकल और अन्य कर्मियों की जरूरत कैसे पूरा करेगा, यह बताए। इसके साथ ही रिम्स टू को लेकर आठ से नौ बिंदुओं पर जवाब मांगे गए थे।

संक्षिप्त समाचार

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बिहार के छात्रों को कराया जाएगा यह कोर्स

पटना, एजेंसी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग और ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए छात्रों की साइबर सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें तथा गृह मंत्रालय के 2 ।5 घंटे के साइबर हाइजीन सर्टिफिकेशन कोर्स में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। सीबीएसई ने स्कूलों को जारी निर्देश में कहा है कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध और सोशल मीडिया धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक करना आवश्यक है। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2 ।5 घंटे के साइबर हाइजीन सर्टिफिकेशन कोर्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रशिक्षण के जरिए सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर खतरों से बचाव की जानकारी दी जाएगी ।इस कोर्स में फिशिंग, फर्जी लिंक, डिजिटल फ्रॉड, ओटीपी और बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया स्कैम तथा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता दी जाएगी, ताकि छात्र ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बच सकें।

बोलेरो में छिपाकर ले जाई जा रही थी 1।24 क्विंटल गांजे की खेप

बेतिया, एजेंसी। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 24 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक बोलेरो वाहन जब्त किया, दो तस्करों को गिरफ्तार किया और फरार हुए दो अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार थानाध्यक्ष अमर कुमार के नेतृत्व में टीम मझौलिया-महना मुख्य सड़क पर चेईलाभार गांव के समीप वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बोलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में छिपाकर रखा गया 1 क्विंटल 24 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मौके से वाहन को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रक्सौल के कौड़िहार चौक निवासी दीपक कुमार (27) और बेतिया आईटीआई निवासी अनुज कुमार (18) को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाइक पर चल रहे दो अन्य तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए।

बिहार में 10 साल बाद बदल सकता है आरक्षण रोस्टर

पटना, एजेंसी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। हालांकि चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन गांवों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को लेकर है। माना जा रहा है कि करीब 10 साल बाद कई पंचायतों में आरक्षण की श्रेणी बदल सकती है। इसका सीधा असर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच के चुनाव पर पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित होगी, इसका फैसला आरक्षण रोस्टर से होता है। यही वजह है कि इस बार हजारों संभावित उम्मीदवार अंतिम सूची का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत राज नियमों के अनुसार पंचायतों में आरक्षण हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह रोटेशन सिस्टम के तहत तय होता है। पिछली बार वर्ष 2016 में आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। अब 2026 में नया चक्र पूरा होने के कारण कई पंचायतों में आरक्षण बदलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो कई सामान्य सीटें आरक्षित हो सकती हैं। वहीं, कुछ आरक्षित सीटें जनरल कैटेगरी में भी आ सकती हैं। इससे कई पुराने जनप्रतिनिधियों और नए उम्मीदवारों की चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल सकती है।

बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में दरभंगा के जाले प्रखंड में पदस्थापित बीडीओ की पत्नी 29 वर्षीय अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा। पुलिस ने कहा कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (स्न्रस्रु) की टीम को भी बुलाया गया है।

बिहार में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज,

सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

मोतिहारी, एजेंसी। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना को लेकर विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरा गया है। निर्माण कार्य का विरोध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत कुल 57 लोगों के खिलाफ पिपराकोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी में 27 लोग नामजद: 57 लोगों में 27 लोगों को नामजद जबकि 30 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने समूह बनाकर निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट भी की।

3 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क परियोजना: यह पूरा मामला कृषि विज्ञान केंद्र के समीप स्थित सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण से जुड़ा है। प्रशासन के अनुसार करीब 14 एकड़ सरकारी भूमि में से लगभग 3 एकड़ जमीन पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी वाटर पार्क परियोजना विकसित की जानी है। लेकिन इस जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

किसानों के समर्थन में सांसद सुधाकर सिंह: किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, इसलिए उनका इस पर अधिकार बनता है और सरकार बिना उचित प्रक्रिया अपनाए जमीन नहीं ले सकती। विवाद ने 3 जुलाई, 2026 को उस समय नया मोड़ ले लिया जब राजद सांसद सुधाकर सिंह स्वयं किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसान सभा में भाग लिया और उसके बाद किसानों के साथ निर्माण स्थल तक पहुंचे।

ट्रैक्टर से पहुंचे सांसद सुधाकर सिंह: इस दौरान सांसद ट्रैक्टर पर सवार होकर विवादित जमीन की जुताई करते भी नजर आए। इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई।

क्या कहती है पुलिस: पुलिस के अनुसार, निर्माण स्थल पर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की तथा मारपीट की गई। इसी आधार पर पिपराकोठी थाना में सांसद समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।

क्या कहता है अंचल प्रशासन: दूसरी ओर, पिपरा कोठी अंचल प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वह गैरमजरूआ जरपेशकी श्रेणी की सरकारी भूमि है। अंचलाधिकारी के अनुसार, सरकार की आवश्यकता नहीं होने के कारण वर्षों तक किसानों को वहां खेती करने दी गई थी, लेकिन इससे किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जब सरकार को भूमि की आवश्यकता होती है, तब उसे वापस लेने का पूरा अधिकार है।

जबरन जमीन अधिग्रहण का आरोप: वहीं, किसान और राजद सांसद सुधाकर सिंह का पक्ष इससे अलग है। सांसद का कहना है कि यदि यह भूमि पहले गैरमजरूआ मालिक की श्रेणी में थी तो इसे बाद में गैरमजरूआ जरपेशकी कैसे घोषित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी कर जबरन जमीन अधिग्रहित की जा रही है। सांसद ने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार का दावा: उधर, प्रशासन का दावा है कि प्रस्तावित वाटर पार्क भारत सरकार की सार्वजनिक हित की परियोजना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना से पूरे क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा, इसलिए विकास कार्य को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई शुरू: फिलहाल पिपराकोठी में वाटर पार्क परियोजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हो गई हैं। एक ओर प्रशासन सरकारी भूमि पर विकास कार्य आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर किसान और विपक्षी दल आंदोलन को और व्यापक बनाने की बात कह रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

घरवालों को कमरे में बंद किया, अलमारी तोड़ी और 40 लाख से ज्यादा का माल लेकर फरार हुए चोर

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। मुजफ्फरपुर जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के बुलबुलवा गांव में शुक्रवार-शनिवार की रात चोरों ने एक किसान के घर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर की पीछे की ग्रिल काटकर अंदर घुसे और परिवार के लोगों को कमरे में बाहर से बंद कर अलमारी का लॉकर तोड़ दिया। चोर 200 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी, नकदी समेत 40 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए।

घटना वार्ड संख्या-1 स्थित बुलबुलवा गांव की है। जानकारी के अनुसार किसान शिव बाबू चौधरी का पूरा परिवार रात में अपने-अपने कमरों में सो रहा था।

इसी दौरान बदमाश घर के पीछे पहुंचे और लोहे की ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश कर गए। किसी को भनक न लगे, इसके लिए चोरों ने सबसे पहले उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसमें गृहस्वामी सो रहे थे।

परिवार को कमरे में बंद करने के बाद बदमाश दूसरे कमरे में रखी गोदरेज अलमारी तक पहुंचे। कटर और अन्य औजारों की मदद से अलमारी का ताला और लॉकर तोड़ दिया।

पीड़ित परिवार के अनुसार चोर लगभग 200 ग्राम सोने के आभूषण, 500 ग्राम चांदी के जेवर, 50 हजार रुपये नकद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चोरी गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य 40 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।शनिवार सुबह जब परिवार की नींद खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद पाया।

बॉयफ्रेंड शादी से मुकरा तो रेलवे ट्रैक पर पहुंची युवती

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। मुजफ्फरपुर में पांच साल पुराने प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत होते-होते बच गया। प्रेमी और उसके परिजनों ने कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इनकार कर दिया। इससे आहत युवती आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। समय रहते सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे ट्रैक से सुरक्षित हटाया और बड़ा हादसा टाल दिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु रेलवे गुमटी के पास की है। जानकारी के अनुसार, युवती मनियारी इलाके की रहने वाली है। करीब पांच वर्ष पहले फेसबुक के जरिए एक युवक से पहचान हुई थी। बातचीत धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। लंबे समय तक दोनों ने अपने रिश्ते की जानकारी परिवार वालों से छिपाकर रखी।

परिजन ने जब युवती की शादी के लिए दूसरे लड़के की तलाश शुरू की तो हर बार प्रेमी को इसकी जानकारी मिल जाती थी। आरोप है कि वह किसी न किसी तरह शादी का रिश्ता तुड़वा देता था। आखिरकार युवती ने अपने परिवार को प्रेम संबंध की जानकारी दी और उसी युवक से शादी करने की इच्छा जताई।

दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और 29 जून को सगाई भी तय हो गई। आरोप है कि इसके बाद युवक और उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। सामाजिक स्तर पर कई बार समझौते की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी।

मानसिक रूप से टूट चुकी युवती शुक्रवार को रामदयालु रेलवे गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल-112 को दी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मुकर्रम अंसारी, बबली कुमारी, रौशन कुमार और विनीत कुमार मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित ट्रैक से हटाकर उसकी जान बचा ली।

नेपाल की 10 महिलाओं ने ली भारतीय नागरिकता की शपथ, गृह मंत्रालय को भेजे गए दस्तावेज

अररिया, एजेंसी। बिहार के अररिया जिले में विवाह के बाद रह रही नेपाल की 10 महिलाओं ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने सभी महिला आवेदिकाओं को विधिवत शपथ दिलाई। ये सभी महिलाएं लंबे समय से यहां अपने परिवारों के साथ रह रही हैं।

दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच: जिला प्रशासन के अनुसार इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले के स्थानीय निवासियों से हुआ है। नागरिकता आवेदन प्रक्रिया के तहत सभी आवेदिकाओं के आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच प्रशासनिक स्तर पर पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

गृह मंत्रालय को सत्यापन: निर्धारित नियमों के तहत अब सभी आवेदनों और अभिलेखों को गहन सत्यापन के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग को भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर जांच पूरी होने के बाद, इन दस्तावेजों को अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। दोनों स्तरों से हरी झंडी मिलने के बाद नागरिकता दी जाएगी।

पारदर्शिता पर विशेष जोर: इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद दूहन ने कहा कि नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकता से जुड़े इन सभी मामलों का समयबद्ध और निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र महिलाओं को सुविधाएं मिल सकें। 'संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकता से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र आवेदिकाओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

नागरिकता अधिनियम के प्रावधान: इन महिलाओं को 'नागरिकता अधिनियम 1955' के विशेष प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जा रही है। इस प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रखंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इससे आवेदिकाओं को आवेदन करने और सहायता पाने में काफी सुविधा मिल रही है।

पात्रता और जरूरी नियम: नागरिकता पाने के लिए महिला का किसी भारतीय नागरिक से वैध विवाह होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसे भारत में कम से कम 7 साल तक सामान्य रूप से निवास करना जरूरी है। वर्तमान में नेपाली मूल की महिलाएं ही इस विशेष नियम के तहत आवेदन करने की पात्र मानी गई हैं।

आवेदन और अंतिम प्रक्रिया: आवेदन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, शपथ पत्र और निवास प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इच्छुक महिलाएं शिविर में जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकती हैं। प्रशासनिक सत्यापन और गृह मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद, महिलाएं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर नागरिक बन सकती हैं।

बिहार एसटीएफ की वांटेड अपराधियों से सीधी मुठभेड़,

पैर में गोली लगने के बाद पकड़े गए दो बदमाश

वैशाली , एजेंसी। बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत बालिगांव थाना क्षेत्र में बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर के बाद दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी भी इस क्रॉस-फायरिंग में घायल हुआ है।

ताजपुर से शुरू हुआ था ऑपरेशन : गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी अमन साहनी और समस्तीपुर निवासी उसके सहयोगी के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, समस्तीपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम को इन अपराधियों के मूवमेंट की सटीक खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम ने समस्तीपुर के ताजपुर इलाके से ही संदिग्धों का पीछा करना शुरू कर दिया।

एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा : समस्तीपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम समस्तीपुर के ताजपुर इलाके से इन अपराधियों का पीछा कर रही थी। भागने के क्रम में जैसे ही अपराधियों का सामना वैशाली जिले के बालिगांव थाना क्षेत्र में पुलिस बल से हुआ, उन्होंने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी घायल होकर मौके पर ही दबोच लिए गए।

लूटपाट के कई मामलों में थे वांछित : पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, पकड़े गए दोनों अपराधी क्षेत्र में लूटपाट की कई गंभीर वारदातों में लंबे समय से वांछित (वांटेड) चल रहे थे। मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों आरोपियों को तत्काल कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है।

मौके पर दलबल पहुंचे एसपी वैशाली : घटना की सूचना प्राप्त होते ही वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा स्वयं दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की विधिक जांच शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे बालिगांव क्षेत्र को अस्थाई रूप से पुलिस छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

अब लखीसराय में घर के पास बनेगा पासपोर्ट! 21 जुलाई से लगेगा 3 दिवसीय मोबाइल वैन शिविर

पटना, एजेंसी। लखीसराय और आसपास के जिलों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। विदेश मंत्रालय की 'पासपोर्ट सेवा-पासपोर्ट आपके द्वार' पहल के तहत 21 से 23 जुलाई, 2026 तक समाहरणालय परिसर, लखीसराय में तीन दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर के जरिए नागरिकों को स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना की ओर से 21, 22 और 23 जुलाई को समाहरणालय परिसर, लखीसराय में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को घर के नजदीक पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराना और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है।

लखीसराय में यह दूसरा पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर होगा। इससे पहले 1 से 3 जुलाई 2025 के बीच आयोजित शिविर को अच्छा प्रतिसाद मिला था। जिले में लगातार बढ़ रही पासपोर्ट की मांग को देखते हुए इस बार फिर विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है।

शिविर का संयुक्त उद्घाटन 21 जुलाई को जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना स्वधा रिज़वी करेंगे। तीन दिनों में कुल 165 आवेदकों को सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रतिदिन 55 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निर्धारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निर्देश- 'नेपाल बॉर्डर पर आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें'

पटना , एजेंसी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में भारत-नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा, प्रशासनिक एवं विकासात्मक विषयों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बॉर्डर एरिया के 7 जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जुड़े हुये थे।

विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश : मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आर्थिक अपराधों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सीमा पर कोई भी गैर कानूनी काम ना हो। किशनगंज जिले में ऐसे 100 उपयुक्त स्थलों की पहचान की जाय जहां उर्दू विद्यालय की स्थापना की जा सके।

भारत-नेपाल सीमा पर कोई भी गैर कानूनी कार्य न हो- मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा की कुल लंबाई 735 किलोमीटर है। इस सीमा पर बिहार के 7 जिले, 70 पुलिस थाना एवं एसएसबी के 194 बीओपी अवस्थित हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर कोई भी गैर कानूनी एवं अनैतिक कार्य न हो, इसे सभी सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उर्वरक एवं मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के बीच नियमित समन्वय बैठक आयोजित की जाय। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर ऐसे व्यक्तियों की पहचान एवं सत्यापन किया जाय, जिनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अचानक असामान्य वृद्धि हुयी हो, ऐसे मामलों की पूरी जानकारी संकलित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

हाई लेवल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा : बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन एवं भारत-नेपाल संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। किशनगंज, मधुबनी एवं पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी, साथ ही अपने-अपने सुझाव भी साझा किये। एसएसबी, आईबी, ईडी, एनसीबी, कस्टम्स, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने भी अपने-अपने सुझाव एवं विभाग से संबंधित की गयी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी।

जी-राम-जी' कानून ग्रामीण विकास का नया रोडमैप'

दरभंगा, एजेंसी। मिथिला हॉर्टिकल्चर क्लस्टर को मिली मंजूरी दरभंगा और मधुबनी के किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह कहना है दरभंगा सांसद एवं लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉ। गोपालजी ठाकुर का। लहेरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा, '100 करोड़ रुपये की इस परियोजना के माध्यम से केला, आम, लीची और मखाना जैसी प्रमुख फसलों से जुड़े करीब 19 हजार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।' सांसद ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा बिहार सरकार के प्रयासों से मिथिला के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है।'

सांसद डॉ। ठाकुर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती, फसल प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), पैकेजिंग और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्य किए जाएं।

उन्होंने किसान चौपाल के जरिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को नई कृषि योजनाओं और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने पर भी जोर दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी नीरज कुमार सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद डॉ। गोपालजी ठाकुर ने बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 'विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी (जीरामजी)' कानून को ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा, 'मनरेगा के लगभग 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर तैयार यह नई व्यवस्था गांवों की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी।

सांसद ने आगे कहा, '6,715 करोड़ रुपये के अंतरिम बजट में राज्य सरकार का 4,500 करोड़ रुपये का योगदान इस योजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई व्यवस्था के तहत केवल अस्थायी कार्यों तक सीमित रहने के बजाय गांवों में बारहमासी ग्रामीण सड़कें, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, जल संचयन के लिए पक्के तालाब और अन्य स्थायी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा।'

रोजगार बढ़ेगा, पलायन होगा कम

डॉ। ठाकुर ने कहा, 'इस नई व्यवस्था से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।' उन्होंने इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम बताया।

संक्षिप्त समाचार

रसोई में राशन नहीं, परिसर में मिली गंदगी पर प्रधानाध्यापिका निलंबित

आगरा, एजेंसी। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के बीच शुक्रवार को डीएम मनीष बंसल ने प्राथमिक विद्यालय छीपीटोला और पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता का औचक निरीक्षण किया। पीएम श्री विद्यालय रोहता में भारी लापरवाही, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में विफलता और खराब शैक्षणिक स्थिति पाए जाने पर नाराजगी जताई और प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुनीता सक्सेना को निलंबित कर दिया। साथ ही शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। वहीं छीपीटोला स्कूल में शैक्षणिक स्तर बेहतरीन मिलने पर शिक्षकों को प्रशस्तिपत्र देने को कहा। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के बाद डीएम सबसे पहले प्राथमिक स्कूल छीपीटोला पहुंचे। वहां उन्होंने कक्षा-3 के बच्चों से संवाद किया और ब्लैकबोर्ड पर स्वयं पढ़ाया। बच्चों के हिंदी-अंग्रेजी की किताब पढ़ने और सही जवाब देने पर उन्होंने पीठ थपथपाई। डीएम ने स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और मिड-डे-मील की गुणवत्ता की भी जांच की। इसके बाद डीएम पीएम श्री विद्यालय रोहता पहुंचे। वहां 14 सदस्यों का स्टाफ होने के बावजूद भारी अव्यवस्थाएं मिलीं। निरीक्षण में रसोई घर में राशन नहीं मिला। परिसर में गंदगी थी और लाखों की लागत से आई नई स्मार्ट टीवी व खेल सामग्री धूल फांकती मिली। बच्चे भी कक्षा के समय बाहर घूमते मिले। शिक्षकों ने बच्चों के साथ मिड-डे-मील खाने से मना कर दिया। प्रधानाध्यापिका के संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर डीएम ने उन्हें निलंबित करने के साथ ही मौके पर बीडीओ बरौली अहीर, एडीओ पंचायत और खंड शिक्षा अधिकारी को तलब कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीएसए राकेश कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

डिविजनल डेंटल लैब के लिए खोज रहे 400 वर्गफीट जमीन

बरेली। दांतों के बेहतर इलाज के लिए अब निजी अस्पताल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। शासन से डिविजनल डेंटल लैब के निर्माण के लिए मांगे गए प्रस्ताव पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में कवर्ड एरिया खोजने की कवायद हुई। डेंटल ओपीडी को लैब बनाने पर मंथन हुआ। एडी एसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित के मुताबिक, जिला अस्पताल में डेंटल ओपीडी चल रही है। डिविजनल लैब में सिर्फ बरेली ही नहीं, मंडल के अन्य जिलों के दंत रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया हो सकेगा। इसके लिए सिर्फ 400 वर्गफीट भूमि ही नहीं, भवन भी चाहिए। अस्पताल में कोई भवन खाली नहीं है। डेंटल ओपीडी के तीन कक्ष, एक कार्यालय का क्षेत्रफल लैब के लिए पर्याप्त पाया गया है। शुक्रवार को डिप्टी सीएमओ डॉ. अमित, साइकोलॉजिस्ट डॉ. आशीष, हॉस्पिटल मैनेजर पूजा चौहान के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कवर्ड एरिया की नापजोख कराकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति पर प्राप्त बजट से आधुनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी। साथ ही, मानव संसाधन भी शासन से मुहैया कराया जाएगा। मंडल स्तर पर डिविजनल डेंटल लैब बनाने की कवायद छह माह से जारी है। सीएमओ ने अब जिला अस्पताल की डेंटल ओपीडी को लैब बनाने पर सहमति जताई है।

सीसीएसयू का दावा...नहीं लीक हुआ आंतरिक परीक्षा का प्रश्नपत्र, पोर्टल पर था केवल प्रैक्टिस टेस्ट

मेरठ, एजेंसी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) प्रशासन ने ऑनलाइन आंतरिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने संबंधी खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर चल रहीं इन सूचनाओं को निराधार, भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है। परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से पहले पोर्टल पर जो सामग्री दिख रही थी, वह वास्तविक प्रश्नपत्र नहीं बल्कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपलोड किया गया एक प्रैक्टिस टेस्ट था। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस बार आंतरिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। छात्रों को इस नई तकनीक और डिजिटल प्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से परीक्षा पोर्टल पर एक मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध कराया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों को लॉगिन करने, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने, स्क्रीन पर प्रश्नों के बीच नेविगेट करने और अंत में उत्तर सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक अभ्यास कराना था। इस प्रैक्टिस टेस्ट में केवल नमूने (सैंपल) के प्रश्न शामिल थे जिनका वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था। परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने बताया कि कुछ लोगों ने इसी प्रैक्टिस टेस्ट को वास्तविक प्रश्नपत्र समझ लिया और सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह फैला दी। उन्होंने साफ किया कि वास्तविक आंतरिक परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत एक बिल्कुल अलग गोपनीय प्रश्नपत्र के माध्यम से आयोजित की गई है। इसलिए पेपर आउट होने या पहले से प्रदर्शित होने के सभी दावे पूरी तरह असत्य हैं।

छह जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक

एजेंडा जारी, सबसे पहले इस्तीफों पर विचार

लखनऊ, एजेंसी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक छह जुलाई को दोपहर तीन बजे मणिराम दास छावनी में होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि की ओर से जारी बैठक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि बैठक के एजेंडे में सबसे पहले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के त्यागपत्र पर विचार होगा। इसके साथ ही राम मंदिर के दान-पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के समक्ष रखी जाएगी।

महंत नृत्यगोपाल दास की अध्यक्षता में होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में मंदिर प्रबंधन की आगामी व्यवस्थाओं पर चर्चा के अलावा वित्त वर्ष 2025-26 के आय-व्यय का लेखा-जोखा और अन्य वित्तीय विवरणों पर भी विचार कर स्वीकृति दी जाएगी। ट्रस्ट ने इसे अत्यावश्यक विषयों पर विचार के लिए अल्प सूचना पर बुलाई गई बैठक बताया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद यह ट्रस्ट की पहली औपचारिक बैठक है।

पहली बार ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के त्यागपत्र आधिकारिक एजेंडे में शामिल किए गए हैं। साथ ही एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट पर भी ट्रस्ट चर्चा करेगा। ऐसे में इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णय न केवल ट्रस्ट के नेतृत्व, बल्कि मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और भविष्य की कार्यप्रणाली की दिशा भी तय कर सकते हैं।

इसलिए देशभर की निगाहें छह जुलाई की इस बैठक पर टिकी हैं।

बैठक सूचना में अंत में निवेदक स्वामी गोविंद देव गिरि, कोषाध्यक्ष का नाम अंकित है, लेकिन पत्र पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं। हालांकि सूचना में उल्लेख है कि इसे अध्यक्ष की अनुमति से जारी किया गया है। ट्रस्ट की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। इससे पहले भी ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय व डॉक्टर अनिल के इस्तीफे की सूचना भी बिना हस्ताक्षर वाला पत्र जारी कर दी गई थी। एजेंडा की सूचना ट्रस्टियों को भेज दी गई है। सवाल है कि बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की अध्यक्षता में होनी है, लेकिन वे लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में मामूली सुधार है। ऐसे में छह जुलाई की बैठक में यदि वे शामिल नहीं होते हैं, तो किसकी अध्यक्षता में होगी।

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दानपात्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों वाले मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिका (पी आई एल) पर संभवतः सोमवार को सुनवाई होगी। मामले की सी बी आई से जांच कराने समेत चढ़ावे की संपत्ति का कैग से ऑडिट कराने की मांग वाली यह पी आई एल को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में इसी 12 जून को दाखिल हुई थी। समय की कमी की वजह से ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान इसपर सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह जनहित याचिका 6 जुलाई की वाद सूची में न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने व्यक्तिगत रूप से यह जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें, कथित गबन मामले की जांच समेत केस दर्ज करने के निर्देश सी बी आई को देने का कोर्ट से आग्रह किया गया है।

बैठक के प्रमुख एजेंडे

- महासचिव चंपत राय एवं ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार
- दान-पात्रों से प्राप्त राशि की गणना पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की जानकारी
- मंदिर प्रबंधन की आगामी व्यवस्थाओं पर विचार
- रिक्त पदों पर चयन के लिए नामों पर विचार
- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक विषयों पर निर्णय

कंट्रोल रूम में आरोपियों ने कई बार डिलीट किए थे सीसीटीवी फुटेज, लेकिन फिर भी मिले साक्ष्य

लखनऊ, एजेंसी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी की करतूत न खुले, इसलिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी से छेड़छाड़ की। कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश की और एक-दो बार इसमें सफल भी हुए। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच में सबूत के तौर पर जितने फुटेज की जरूरत थी, उतने मिल चुके हैं।

मंदिर में चढ़ावे की जहां पर गणना की जाती थी, वह पूरी जगह सीसीटीवी कैमरों की जद में है। यह बात आरोपियों को पता थी। जो जानकारी उन्हें नहीं होती थी, वह गणना इंचार्ज सुभाष व टिन्नू यादव से मिल जाती थी। इस तरह गणनाकर्मी मंदिर के कोने-कोने से वाकिफ थे। जब ये सभी रकम पार करते थे, तो उस दौरान सभी लोग एक कर्मी को घेरकर खड़े हो जाते थे, ताकि पूरी तरह कैमरे की जद में न आएं। लेकिन, तब भी कैमरे में कैद होते गए। पुलिस की पूछताछ व जुटाए गए साक्ष्यों से पता चला कि आरोपी सबूत मिटाने का प्रयास करते थे, ताकि वह पकड़े न जाएं। इसलिए वह खुद कंट्रोल रूम में कई बार गए और सीसीटीवी से छेड़छाड़ की। यही वजह है कि कंट्रोल प्रभारी व वहां तैनात कर्मी भी सवालों के

घेरे में हैं।

कंट्रोल रूम की करते थे निगरानी: आरोपी बखूबी जानते थे कि उनकी करतूत कैमरों में कैद हो रही है। तब भी वह रुपये पार करते रहे। सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया कि गणना के वक्त जब आरोपी रकम पार करते थे, तो कई बार गणना इंचार्ज कंट्रोल रूम की निगरानी करता रहता था ताकि वहां पर कोई न जाए। अगर जाए, तो वह उसका ध्यान भटका सके। टिन्नू ने भी ये काम किया है। मतलब, हर वह प्रयास करते थे, जिससे वह पकड़े न जा सकें।

अविनाश ने उगले राज, टिन्नू सुभाष की भूमिका की पुष्टि की : अविनाश से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। अविनाश ने बताया कि उसके साथ टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत थी, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं था। टिन्नू कहता था कि कहीं कुछ नहीं होगा। फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। बाकी यहां कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि टिन्नू की ही जिम्मेदारी निगरानी की थी।

दो साल तक बनाया हवस का शिकार, बहन ने सहेलियों की मदद से बनाया कुकृत्य का वीडियो

फतेहपुर, एजेंसी। फतेहपुर जिले में नाबालिग बहन को डरा-धमकाकर बड़ा भाई दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने परिजन को आपबीती बताई लेकिन उन्होंने मानने से इन्कार दिया। इस पर उसने सहेलियों की मदद से खुद का वीडियो बनवाया और हकीकत परिजन को दिखाई।

छोटी भाभी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी भाई की तलाश में छापा मारा, लेकिन वह फरार हो गया। देर रात पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है, जिससे जानकारी की जा रही है।

जबरन शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए

थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 25 वर्षीय भाई पत्नी की हत्या में करीब तीन साल पहले जेल गया था। करीब दो साल पहले जेल से छूटा था। किशोरी का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद भाई ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए।

कुछ दिन पहले परिजन को आपबीती बताई

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह बदनामी और दहशत की वजह से लंबे समय तक चुप रही। कुछ दिन पहले परिजन को आपबीती बताई। वह भी मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर उसने छोटी भाभी और सहेलियों को आपबीती बताई।

शारीरिक शोषण का वीडियो बनवाया

भाभी ने युवक का विरोध किया। विरोध पर छोटी भाभी को भी युवक ने पीट दिया। इस पर किशोरी ने सहेलियों के जरिये कुछ दिन पहले ही शारीरिक शोषण का वीडियो बनवाया। वीडियो के आधार पर छोटी भाभी ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की।

हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही

प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को देर शाम पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है।

50 रुपये दीजिए तभी खिंचेगा लाइसेंस के लिए फोटो, आरटीओ में कैमरे के सामने हो रही वसूली

वाराणसी, एजेंसी। आजमगढ़ नगर के हर्रा की चुंगी क्षेत्र में संचालित आरटीओ कार्यालय अब गंभीरवन में बनी खुद की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। कार्यालय शिफ्ट होने के बाद यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लाइसेंस के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसका फायदा उठाकर लोगों से वसूली भी हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रतिदिन 120 का स्लाट बुक होता है। जहां लोगों की फोटो खींची जाती है वहां बिना 50 रुपये दिए फोटो नहीं खींचा जा रहा है।

आरटीओ कार्यालय में वैसे तो सारा काम विभाग खुद देखता है लेकिन लाइसेंस पर लगने वाले फोटो को खींचने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है। उक्त कंपनी के कर्मचारी आरटीओ आफिस के गेट

पर ही एक कमरा बना है उस कमरे में बैठकर लोगों की फोटो खींचने का काम करते हैं।

शुक्रवार को फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की भींड़ लगी हुई थी। कर्मचारी अपना काम करने में मशगूल थे। फोटो खींचने के बाद वह लोगों से 50 रुपये तक की वसूली कर रहे थे।

इस प्रकार देखा जाए तो यहां प्रतिदिन लोगों से 6000 रुपये की वसूली की जाती है।

एक व्यक्ति ने जब कहा कि उसने फीस जमा कर दिया है तो फिर किस बात का पैसा यहां लग रहा है तो उसे बताया गया कि आपने फीस जमा की है। यहां फोटो खिंचवाने का पैसा लगता है। इसे देना ही पड़ेगा। मजबूरी में उक्त व्यक्ति ने भी भी 50 रुपये दिए और फोटो खिंचवाकर चलता बना।

ट्रैक पर जा रहे लोगों को लगाई फटकार बोला साहब देख रहे हैं

इस दौरान जब दो लोग टेस्टिंग ड्राइव ट्रैक को देखने के लिए ट्रैक पर पहुंच गए तभी एक व्यक्ति ने उन्हें कड़कदार आवाज में रोका कहां जा रहे हैं, वापस आइए। हर तरफ सीसीटीवी लगा है और साहब बैठे देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब साहब टेस्टिंग ड्राइव ट्रैक पर नजर रखे हैं तो उन्हें अपने परिसर में हो रही यह वसूली दिखाई क्यों नहीं देती है।

- *लाइसेंस की फीस जमा होने के बाद और कोई शुल्क कहीं नहीं लगता है। फोटो के लिए पैसा लग रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं है। वह लोग कंपनी के आदमी हैं। फिर भी हम पता करते हैं, अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। हम वहां भी सीसीटीवी लगवाएंगे।*

– **विष्णुदत्त मिश्रा,** एआरटीओ प्रशासन।

सीसीटीवी कैमरा लगा फिर भी नहीं आ रहे बाज

उक्त कमरे के एक कोने में एक सीसीटीवी कैमरे के साथ उसका डीवीआर भी लगा हुआ है। इसके बाद भी कर्मचारी लोगों से पैसे मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं। वह सबके सामने पैसा लेकर अपनी जेबों में रखते हुए नजर आए।

मेरठ में भाई-बहन को बनाया बंधक, युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म

मेरठ, एजेंसी। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र से एक अत्यंत निंदनीय घटना सामने आई है। सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से भैंस का सौदा करने आए भाई-बहन को दो चचेरे-तहेरे भाइयों ने बंधक बना लिया। आरोप है कि आरोपियों ने भाई को जान से मारने की धमकी देकर बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुंडाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, दो दिन पूर्व सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती अपने भाई के साथ मुंडाली में भैंस का सौदा करने के लिए मुंडाली निवासी रिजवान और मारूफ के यहां आई थी। बताया गया कि दोनों भाई लगभग पांच वर्षों से डेयरी का काम कर रहे हैं और गांव में दूध की सप्लाई भी करते हैं।

पीड़िता ने बताया कि जब वे मुंडाली में डेयरी पर पहुंचे, तो दोनों भाइयों ने बहन-भाई को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद भाई को हथियार के बल पर बंधक बनाकर रिजवान और मारूफ ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि विरोध करने पर भाई-बहन को बेरहमी से पीटा गया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

शुक्रवार शाम पीड़ित भाई-बहन मुंडाली थाना पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी रिजवान और मारूफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। थानाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आरोप सही पाए गए तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

जिस बाथरूम में पति की हत्या कर दफनाया, वहां रोज नहाती थी पत्नी, जेठ को बताया खौफनाक सच

आगरा, एजेंसी। पुलिस के अनुसार, महिला ने कथित रूप से पति की हत्या के बाद शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया और कई दिनों तक उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही। मामला तब खुला जब उसने जेठ को बुलाकर कथित तौर पर बताया कि उसका पति बाथरूम के फर्श के नीचे दफन है।

आगरा के थाना सिकंदरा के दहतोरा में पत्नी ने बेरहमी से पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को बाथरूम में दफना दिया। इतना ही नहीं मिस्त्री को बुलाकर फर्श बनवा दिया। पुलिस के अनुसार रूबी ने पति की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी की थी। जिस बाथरूम में पति को गाढ़ दिया था। उसमें ही रोजाना नहाती भी थी।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र नींद की गोलियां खाता था। रूबी ने 18 मई को उसको खीर में मिलाकर नींद की 16 से 20 गोलियां दी थीं। उसकी मौत हो गई। वह उसे खींचकर बाथरूम में ले गई। बाथरूम में इंडियन सीट लगी थी। वह ऊपर थी। फर्श नीचे था। इस पर शव को फर्श को थोड़ा और खोदकर डाल दिया। बाद में मिट्टी और गिट्टी मंगवाई थीं। इससे शव को दफना दिया। इसके बाद उस पर पक्का फर्श कर दिया। वह पति की हत्या के बाद जितने दिन घर में रही, जिस बाथरूम में शव दफनाया, उसी में नहाती भी थी। पड़ोस के लोग जब भी पति के बारे में पूछते थे, परेशान होने का नाटक करती थी। पूछने पर रोने भी लगती थी।

जेठ को घर बुलाकर बोली, बाथरूम में दो फीट नीचे हैं पति : अनिल ने बताया कि भरतपुर में बैंक स्टेटमेंट से शक होने पर भाभी रूबी से बृहस्पतिवार सुबह बात की थी। उनसे कहा था कि पेंशन तो आपने ले ली है। मुझे क्यों नहीं दी। रकम का क्या कर रही हो। यह बता दो। मगर वो चुप हो गई। उसने कहा कि भाई के बारे में बता दो। रूबी ने फिर भी कुछ नहीं बताया। शुक्रवार सुबह 6 बजे फोन करके जेठ को बुलाया। कहा कि पति घर पर हैं। आकर बात कर लो। जब अनिल पहुंचे तो उसने बताया कि बाथरूम में हैं। इस पर अनिल ने वहां जाकर देखा। मगर कोई नजर नहीं आया। इस पर रूबी ने कहा कि दो फीट नीचे हैं। इस पर ही उन्होंने पुलिस को जानकारी दी।

पड़ोसी बोले, पूरी तैयारी से ठिकाने लगाया शव, नहीं लगी भनक : रूबी के बारे में जानकर पड़ोसी भी हैरत में पड़ गए। उनका कहना था कि शराब की वजह से पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। शराब की वजह से पति ने डिलीवरी बाय की नौकरी छोड़ दी थी। रूबी ही घर में कपड़े सिलने का काम करती थी। उसे जो रुपये मिलते थे, उसे पति झगड़ा करके छीन लेता था। कई बार लोगों ने समझाने का प्रयास किया। मगर वो मानने को तैयार नहीं हुआ। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि रूबी उसकी हत्या कर देगी। शव को जिस तरह से ठिकाने लगाया, उससे यही लग रहा है कि उसने कई दिन पहले तैयारी कर ली थी। इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगी।

24 साल पहले आगरा आया था परिवार : पुलिस के अनुसार, मूलरूप से भरतपुर के रंजीत नगर निवासी राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। 24 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद आगरा आ गए थे। सिकंदरा के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में रहने लगे। 14 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। सुरेंद्र उनका छोटा बेटा था। बड़े बेटे अनिल ऑटो चालक हैं और वायु विहार, शाहगंज में रहते हैं। सुरेंद्र रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी 16 साल पहले रूबी से हुई थीं। दो बेटियां प्राची (15) और सिद्धि (9) हैं। सुरेंद्र की मां कमला भी साथ ही रहती थीं।

पेंशन के पैसों के लिए हुआ झगड़ा : पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र की मां को पति की पेंशन के 32 हजार रुपये मिलते थे। रूबी डेबिट कार्ड और पासबुक अपने पास रखती थी। पेंशन की रकम से वह जेठ अनिल को 10 हजार रुपये देती थी। जून में रूबी ने अनिल को पेंशन की रकम नहीं दी। कहा कि पेंशन नहीं आई है। अनिल बृहस्पतिवार को मां को भरतपुर लेकर गए। पेंशन के बारे में जानकारी की तो पता चला कि पेंशन खाते में भेजी जा चुकी है। अनिल ने घर पहुंचकर रूबी से शिकायत की तो दोनों में झगड़ा हुआ।

पुलिस से बोली, पति ने कर ली थी आत्महत्या : आरोपी रूबी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वह बार-बार बयान बदलने लगी। पहले उसने नींद की गोली देने की बात कही। फिर कहा कि पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घबराकर उसने शव को दफना दिया। कहा कि बाथरूम का फर्श कमरे के फर्श से दो से तीन फीट नीचे था, इसलिए शव को उसमें डाल दिया। इसके बाद मिट्टी लाकर डाल दी और मिस्त्री बुलाकर फर्श पक्की करवा दी। इससे किसी को शक नहीं हुआ। वह घर में भी आराम से रह रही थी। हालांकि, पुलिस को शक है कि घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दे सकता।

गहनता से की जा रही जांच : डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पति की हत्या के बाद पत्नी ने शव को घर के बाथरूम में दफना दिया था। आरोपी रूबी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उसने बताया कि आए दिन शराब पीकर झगड़े से तंग आकर उसने वारदात को अंजाम दिया। यह भी देखा जा रहा है कि घटना में कोई और तो शामिल नहीं है। हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है।

राजस्थान-हिमाचल में खूब बरसे बादल

मुंबई-गुजरात में मानसून का कहर

मुंबई, अहमदाबाद, एजेंसी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही शुक्रवार को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जमकर वर्षा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ता दिखा।

राज्य के 50 से अधिक जिलों में छिटपुट वर्षा हुई है। वज्रपात की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य झुलस गए। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी वर्षाजनित हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। प्रेट्र के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार 'अल नीनो' प्रभाव के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और 'संभावित सूखे की स्थिति' से उत्पन्न हालात पर लगातार नजर रख रही है।

गुजरात के राजकोट और सूरत में बारिश के कारण जलभराव

कृषि और अन्य संबंधित मंत्रालयों को 'सतर्क' रहने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी हुई है। गुजरात के राजकोट और सूरत में बारिश के कारण जलभराव हो गया। लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में अगले तीन दिन तक केवल छिटपुट बारिश, धूप और उमसभरी गर्मी का असर रहने की संभावना है। छह जुलाई से मानसून के दोबारा सक्रिय होने और सात व आठ जुलाई को प्रदेशभर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को सबसे अधिक 99.8 मिमी वर्षा कानपुर में रिकॉर्ड की गई। इससे कई इलाकों में जलभराव के कारण करीब सात घंटे तक यातायात बाधित रहा। दुकानों और कार्यालयों में पानी भर गया। एक चार मंजिला अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भरने से जमीन धंस गई और इमारत टेढ़ी हो गई। 80 फीट रोड सहित कई सड़कों पर धंसाव हुआ, पेड़ उखड़ गए और फूलबाग में आर्डिनेंस फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई।

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भरा पानी

राजस्थान में करीब एक सप्ताह की देरी से पहुंचे मानसून ने गुरुवार रात से शुक्रवार तक जोरदार दस्तक दी। 22 जिलों में जमकर वर्षा हुई। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में करीब ढाई इंच वर्षा दर्ज की गई। डूंगरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो सगे भाई झुलस गए, जिनमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई।

जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में भी बारिश का पानी ट्रामा सेंटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर में भर गया। जलभराव के कारण माइनर ओटी के मरीजों को दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करना पड़ा। लगातार बारिश से दिन के तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

मुंबई में पांच घंटे में 70 मिमी से अधिक बारिश
मुंबई में शुक्रवार को लगातार बारिश जारी रही। शहर के कई क्षेत्रों में केवल पांच घंटे में 70 मिलीमीटर (मिमी) से अधिक वर्षा दर्ज की गई।

पीएम का फर्जी वीडियो अपलोड़ करने वाले पर मुकदमा दर्ज

जयपुर, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआइ जनरेटेड वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड़ किया गया है। इस मामले में जयपुर के भाजपा प्रवक्ता और वकील खेमचंद शर्मा ने मुहाना पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शर्मा का आरोप है कि फेसबुक पर जयपुर के कार्तिकेय भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने पीएम मोदी का एआइ जनरेटेड वीडियो अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है। यह वीडियो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत है। यह वीडियो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। यह सैंवधानिक पद पर बैठे पीएम के खिलाफ अविश्वास की भावना पैदा करता है। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित देश के नेता की छवि धूमिल की जा रही है।

सक्षिप्त समाचार

सरकार का बड़ा फैसला

सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम खत्म, नया टाइम-टेबल लागू

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लागू विशेष व्यवस्थाओं को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्राम होम व्यवस्था वापस लेने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के कार्यालयों के कार्य समय में भी संशोधन किया गया है।

देखें नया टाइम-टेबल

अब सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों के लिए पहले से लागू समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा स्थिति सामान्य होने और प्रशासनिक कार्यों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नए आदेश लागू होने के बाद सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्य करेंगे।

बच्ची को गोद लेकर आस्ट्रेलिया ले जाना चाहते थे माता-पिता

अटक गया था एनओस

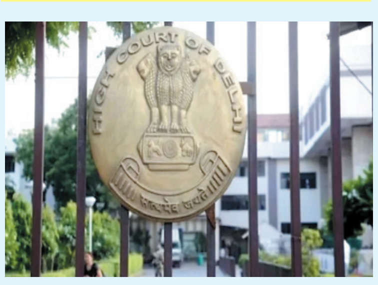

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल (ओसीआई) के एक दंपती को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) को उनकी गोद ली हुई बच्ची के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। यह एनओसी मिलने के बाद बच्ची के आस्ट्रेलिया जाने और वहां उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

मामला यह था कि दंपती ने भारत में हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए) के तहत बच्ची को गोद लिया था। लेकिन जब उन्होंने सीएआरए से एनओसी मांगा तो प्राधिकरण ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि विदेश में रहने वाले दंपती के दत्तक ग्रहण के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और आस्ट्रेलियाई सरकार का जरूरी प्रायोजन पत्र नहीं दिया गया। दंपती ने हाई कोर्ट को बताया कि आस्ट्रेलिया, भारत में एचएएमए के तहत हुए ऐसे दत्तक ग्रहण को अलग श्रेणी का मामला मानता है। इसलिए वहां की सरकार इस तरह का स्पान्सरशिप लेटर जारी ही नहीं करती। ऐसे में सीएआरए की बताई शर्त पूरी करना उनके लिए संभव नहीं था।

अब घर बैठे करें आवेदन, 60 दिनों में मिलेगी सब्सिडी की राशि

- दिल्ली सरकार ने ईवी पोर्टल किया लॉन्च

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ हर दिल्लीवासी तक पहुंचाने के लिए आज आधिकारिक पोर्टलका शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब नागरिकों को सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए घर बैठे आसानी से आवेदन करने की सुविधा मिल गई है। नए पोर्टल के माध्यम से लोग ईवी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं और सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकतम 60 दिनों के अंदर प्रोत्साहन राशि सीधे अपने बैंक खाते में के जरिए प्राप्त कर सकेंगे।

दिल्ली में सरकारी जमीन पर पार्किंग माफिया का कब्जा

नईदिल्ली, एजेंसी। यमुनापार में अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाकर दिल्ली नगर निगम के आरपी सेल के अधिकारियों को बेनकाब किया। किस तरह से पार्किंग माफिया के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर अवैध पार्किंग करवाकर वसूली का खेल चल रहा था। माफिया ने न्यू उस्मानपुर थाने के पास डीएम कार्यालय की जमीन पर भी करीब एक वर्ष से कब्जा किया हुआ था। डीएम अजय कुमार ने सख्त तेवर दिखाते हुए निगम से जमीन को खाली करवाया।

- **कुछ वाहनों को निगम ने जब्त किया-** उस्मानपुर थाने के पास डीएम का कार्यालय बनना प्रस्तावित है। एक हजार गज से अधिक जमीन यहां खाली पड़ी हुई है। डीएम की टीम अपनी जमीन पर पहुंची। निगम व यातायात पुलिस को मौके पर बुलवाया। जमीन पर अवैध पार्किंग धड़ल्ले से चलती हुई मिली। यहां करीब सौ से अधिक वाहन खड़े हुए थे। डीएम की टीम ने वाहनों के पहियों की हवा निकाली। यातायात पुलिस ने 92 वाहनों के चालान किए। कुछ वाहनों को निगम ने जब्त किया।
- **निगम पर उठ रहे सवाल-** शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर पांचवा पुश्ता, शास्त्री पार्क ठेके के पास, खजूरी फ्लाईओवर के नीचे पीडब्ल्यूडी, डीडीए की जमीनों पर

धड़ल्ले से अवैध पार्किंग चल रही है। डीएम कार्यालय की जमीन पर कार्रवाई होने के बाद सवाल उठ रहे हैं आखिर इन विभागों की सरकारी जमीनों को निगम कब खाली करवाएगा। पार्किंग माफिया पर कार्रवाई कब होगी। शास्त्री पार्क में नाले के ऊपर अवैध पार्किंग चल रही है, आरोप है बिजली भी चोरी हो रही है। इस मामले में निगम की आरपी सेल उपायुक्त कनिका सिंह से बात करने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया।

सरकारी जमीन पर दोबारा पार्किंग न हो जाए

कार्रवाई की पूरी मॉनिटरिंग डीएम ने खुद की। डीएम के सख्त संदेश थे अगर उनके कार्यालय के कर्मचारियों ने जरा भी गड़बड़ की तो उनकी नौकरी जा सकती है। प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि प्रशासन ने न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के लिए कहा तो पुलिस ने कानून का पाठ पढ़ा दिया। कहा माफिया के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज होगी तो यहां खड़े वाहनों को जब्त करना होगा, सभी केस प्रापर्टी हो जाएंगे। प्रशासन ने पुलिस को चेताया है कि सरकारी जमीन पर दोबारा पार्किंग न हो जाए।

भीषण गर्मी के बावजूद भी नहीं रुकेगा जश्न, ट्रंप देंगे संबोधन

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका अपने 250वें स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक जश्न मना रहा है। हालांकि वॉशिंगटन और पूर्वी अमेरिका के कई हिस्सों में भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रमों के समय में बदलाव किया गया है। इसके बावजूद सैल्यूट टू अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन, सैन्य प्रदर्शन और भव्य आतिशबाजी तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। वहीं, ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्यापर देशवासियों को संदेश देते हुए अमेरिका के इतिहास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी जोर दिया।

आयोजकों ने बताया कि वॉशिंगटन में सक्रिय हीट एडवाइजरी को देखते हुए सैल्यूट टू अमेरिका समारोह के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। इसका मकसद लोगों को अत्यधिक गर्मी से बचाना है। ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर और फीफा फैन जोन अब दोपहर 12 बजे से खुलेंगे और कार्यक्रम समाप्त होने तक खुले रहेंगे। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट परिसर को भी पहले की तुलना में देर से खोला जाएगा ताकि लोगों को लंबे समय तक धूप में इंतजार न करना पड़े। आयोजकों ने साफ कहा कि समारोह जारी रहेगा, लेकिन लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पूरे आयोजन स्थल पर मुफ्त पेयजल वितरण केंद्र बनाए गए हैं। पानी भरने (रिफिल) के स्टेशन लगाए गए हैं। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कूलिंग टेंट तैयार किए गए हैं। वातानुकूलित (एयर कंडीशंड) बसों की व्यवस्था की गई है। 15 एयर कंडीशंड मंडप बनाए गए हैं, जहां लोग आराम कर सकेंगे। अतिरिक्त मेडिकल टीम और चिकित्सा सहायता तैनात की गई है। धुंध वाले कूलिंग क्षेत्र (मिस्टिंग एरिया) और छायादार विश्राम स्थल बनाए गए हैं। प्रवेश को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच व्यवस्था की गई है। लोगों से हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की गई है। समय-समय पर छांव या ठंडी जगह पर आराम करने की सलाह दी गई है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में क्या होगा खास? नेशनल मॉल के

ऊपर सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन शुरू होगा। नासा के विमान भी हवाई प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। अमेरिकी तटरक्षक बल (यूएस कोस्ट गार्ड) अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर, वायुसेना के लड़ाकू और बमवर्षक विमान उड़ान भरेंगे। मरीन कॉर्प्स और अमेरिकी नौसेना के विमान भी हिस्सा लेंगे। मशहूर एरोबेटिक टीम ब्लू एंजेल्स और थंडरबर्ड्स प्रदर्शन करेंगी। एफ-22 रैप्टर, बी-1 बमवर्षक और एयर फोर्स वन भी फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे। सैल्यूट टू अमेरिका' का मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा।

नेतन्याहू के निशाने पर थे ईरानी वार्ताकार? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर आ गया इस्राइल का बयान

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने उस मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका को आशंका थी कि इस्राइल ईरान के वरिष्ठ वार्ताकारों को निशाना बना सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस रिपोर्ट को फेक न्यूज और हकीकत से पूरी तरह अलग बताते हुए कहा कि इसमें किए गए दावे वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। इस बयान के बाद एक बार फिर मध्य पूर्व की कूटनीतिक हलचल और इस्राइल-ईरान संबंध चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मामला उस रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया कि इस साल इस्लामाबाद वार्ता के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यह आशंका थी कि इस्राइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि 8 अप्रैल के युद्धविराम के बाद के हफ्तों में इस्राइल ऐसी योजना पर विचार कर सकता था। इसी आशंका के चलते अमेरिका ने कथित तौर पर क्षेत्र के कुछ देशों के माध्यम से तेहरान तक अप्रत्यक्ष संदेश पहुंचाया, ताकि ईरानी नेतृत्व को संभावित खतरे से आगाह किया जा सके। हालांकि रिपोर्ट में इन दावों को अधिकारियों के हवाले से पेश किया गया था। इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरानी वार्ताकारों को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा, 'हमेशा की तरह ईरानी वार्ताकारों को लेकर प्रकाशित ताजा खबर फेक न्यूज है। यह वास्तविकता की पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी है।'

मैं अपने बारे में लिखी रोचक खबर पढ़ता हूं, ट्रंप ने बताया कैसे बिताते हैं व्हाइट हाउस में समय?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वैंस के पॉडकास्ट में शामिल हुए। यहां वे अपने शरीर और व्हाइट हाउस में अपना समय कैसे बिता रहे है। इसके बारे में बताया। ट्रंप ने वैंस के 'स्टोरीटाइम विद द सेकंड लेडी' पॉडकास्ट में भाग लिय। जिसे शुक्रवार को ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन की बच्चों की किताब 'प्रेसिडेंट्स प्ले!' पढ़ी, जिसमें राष्ट्रपतियों को खेल का आनंद लेते हुए और व्हाइट हाउस और उसके मैदानों का मनोरंजन के लिए उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। वहीं, जब वैंस ने ट्रंप से पूछा कि क्या राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें मनोरंजन के लिए पढ़ने का पर्याप्त समय मिलता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे ज्यादातर अखबार ही पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं आमतौर पर अपने बारे में लिखी गई कहानियां पढ़ता हूं।' जैसे ही ट्रंप बच्चों की किताब के पन्ने पलट रहे थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में टिप्पणियां कीं। कुछ चुटकुले सुनाए और व्हाइट हाउस परिसर में बन रहे अपने विशाल भोज कक्ष का प्रचार भी किया। उन्होंने लिंडन जॉनसन को कठोर व्यक्तित्व, रोनाल्ड रीगन को उच्च गुणों वाला व्यक्ति और आपके पिता की तरह राष्ट्रपति बताया। वहीं, जॉन एफ. कैनेडी को दूसरे सबसे आकर्षक राष्ट्रपति के रूप में वर्णित किया। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनके अनुसार सबसे आकर्षक राष्ट्रपति कौन था। रिचर्ड निक्सन, जो वाटरगेट कांड में फंसने के बाद पद से इस्तीफा देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, 'शायद खुद ही मुसीबत में फंस गए थे।' महामंदी के दौरान राष्ट्रपति रहे हर्बर्ट हूवर को पुस्तक में 'हूवर बॉल' नामक एक खेल खेलते हुए दर्शाया गया है, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा। 'यह उनके लिए अर्थव्यवस्था से भी बेहतर साबित हुआ।' ट्रंप के लंबे समय से उपहास का निशाना रहे बराक ओबामा को बास्केटबॉल खेलते हुए चित्रित किया गया था।

ब्रिटेन में हिंदू समुदाय को झटका, चर्च और मुस्लिम समूह को दी गई पूजा-अर्चना के लिए मिली जमीन; गैराज में रखीं मूर्तियां

लंदन, एजेंसी। कैम्ब्रिजशायर में रहने वाले ब्रिटिश हिंदुओं की उस कोशिश को झटका लगा है जिसके तहत वे काउंटी में अपनी पहली पूजा-स्थली बनाना चाहते थे। स्थानीय काउंसिल ने नॉर्थस्टो शहर में धार्मिक कार्यों के लिए जमीन का एक टुकड़ा एक हिंदू चैरिटी को देने के बजाय एक चर्च और मुस्लिम समूह को दे दिया।

साउथ कैम्ब्रिजशायर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने नॉर्थस्टो चर्च नेटवर्क को 999 साल के लिए 0.2 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी है, जिसके लिए उन्हें बहुत ही मामूली किराया देना होगा।

हिंदू समाज नॉर्थस्टो ने भी जमीन के लिए बोली लगाई थी और वहां एक मंदिर के साथ-साथ अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए एक सेंटर और वेलबीइंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन बोली का आकलन करने वाले काउंसिल अधिकारियों ने हिंदू समाज की बोली को 65त्न और एनसीएन की बोली को 81त्न अंक दिए, इसलिए जमीन एनसीएन को मिलेगी।

एनसीएन के प्रस्ताव में नॉर्थस्टो के मुसलमानों को एक मुख्य किराएदार (एंकर टेनेंट) के तौर पर शामिल करने की बात है, जिनके लिए अपना इस्लामिक प्रार्थना कक्ष और शिक्षा केंद्र होगा।

कैम्ब्रिजशायर में एक भी मंदिर नहीं: कैम्ब्रिजशायर में कई चर्च और मस्जिदें हैं, लेकिन एक भी मंदिर नहीं है। पूजा-अर्चना के लिए हिंदुओं को बर्मिंघम या वेम्बली तक दो घंटे का सफर करना पड़ता है। वे ऐसी सामुदायिक जगहों को तुरंत किराए पर नहीं ले सकते, जिससे त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर मूर्तियों को कैरी बैग में भरकर गैरेज में रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान उनमें से कई क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। एचएसएन ने क्या कहा? एचएसएन की चेयर अपर्णा निगम-सक्सेना ने कहा, हमें बहुत निराशा है कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। हमें इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और मजबूती को लेकर कई सवाल हैं।

उन्होंने कहा कि वे अपील करने के बारे में सोच रहे हैं। एचएसएन की बोली को कई वजहों से कम आंका गया, जिसमें फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की कमी भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि यह एक अहम बात है। उन्होंने कहा, अगर वे हमारे आर्किटेक्ट से तैयार कोटेशन देखना चाहते थे तो उन्हें हमें गाइडलाइंस देनी चाहिए थीं।

संपादकीय | सरकार फिर ला सकती है नया संविधान संशोधन

देश की राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के मसले पर लंबे समय से बहस चलती रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, ताकि सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पांच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था।

इसमें कोई दोराय नहीं कि भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का बढ़ता दखल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर कई बार ऐसे लोग भी चुनकर संसद या विधानसभाओं में आ जाते हैं, जिन पर जघन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप होता है। अक्सर सामने आने वाली रिपोर्ट में खासी संख्या में दागी जनप्रतिनिधियों के विधायिका में पहुंचने का ब्योरा होता है, जिस पर सभी दल चिंता जताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट न देने को लेकर किसी के भीतर कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखती। दूसरी ओर, चुनाव आयोग भी इस मसले पर कोई स्पष्ट रुख अख्तियार नहीं करता है।

इस लिहाज से देखें, तो सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ाने से लेकर लोकतंत्र में नैतिकता और शुचिता सुनिश्चित किए जाने के लिए एक सख्त नियमन वक्त की जरूरत है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नया कानून देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर विपरीत प्रभाव डालने वाला न हो। दरअसल, विपक्षी दलों की ओर से प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है, जिसमें किसी आरोप के बाद दोषसिद्धि के बजाय सिर्फ हिरासत के आधार पर दंडित किए जाने की व्यवस्था है।

आशंका यह जताई जा रही है कि सत्ताधारी दल की ओर से जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। ऐसे में चुनी हुई सरकारों के सामने भी अस्थिरता का संकट पैदा हो सकता है। जाहिर है, देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कानून बने, उसमें अपराधों की प्रकृति स्पष्ट किए जाने से लेकर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि महज बदले या किसी सरकार को अस्थिर करने की मंशा से इसका दुरुपयोग न हो सके।

15 हजार से ज्यादा उपग्रह के बीच बढ़ रहा अंतरिक्ष कचरा

पृथ्वी की कक्षा में जिस रफ्तार से अंतरिक्ष कचरा बढ़ रहा है, उसका अनुमान उन देशों ने नहीं लगाया होगा, जो संचार संबंधी जरूरतों और सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्षों से उपग्रह भेजते रहे हैं। इन कचरों की वजह से फिलहाल पृथ्वी के लिए जोखिम पैदा होने की आशंका नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में खतरा नहीं बढ़ेगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल, अंतरिक्ष मलबे को साफ करने में न तो किसी की रुचि है और न ही इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कारगर साबित हुई है। खबरों के मुताबिक, अंतरिक्ष में दस सेंटीमीटर से बड़े 36 हजार टुकड़े तैर रहे हैं, जबकि इसके कणों की संख्या करोड़ों में है। इस पूरे मलबे का वजन 13 हजार टन से अधिक है। विचित्र बात है कि तमाम देश सैन्य, संचार, कृषि, मौसम और खुफिया जरूरतों के लिए अंतरिक्ष में अपने उपग्रह तो भेजते हैं, लेकिन उनकी मियाद खत्म होने के बाद उनके निपटान की कोई

तैयारी नहीं करते। कचरे की समस्या इसी वजह से बढ़ी है। चिंता की बात यह है कि कई निजी कंपनियां भी व्यावसायिक उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रही हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर उनके पास भी कोई ठोस योजना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपना दबदबा कायम करना है। नतीजा यह है कि इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की संख्या 15 हजार से अधिक हो चुकी है। इनमें 10 हजार उपग्रह तो स्पेसएक्स कंपनी के हैं, जो भविष्य में बड़ी संख्या में और उपग्रह भेजने की योजना बना रही है। इससे आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष कचरे की मात्रा बेतहाशा बढ़ेगी। ये इसलिए खतरनाक बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये करीब सात किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं। इस कचरे को निपटाने के मौजूदा तरीके भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में धकेले जाने के बाद ये जल तो जाते हैं, लेकिन इससे कार्बन कण पैदा होने के कारण ओजोन परत पर असर पड़ता है। आखिरकार इसकी कीमत मनुष्यों को ही चुकानी पड़ेगी। इस कचरे को साफ करने की ठोस योजना नहीं बनी, तो अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक आशंका के बादल मंडराते रहेंगे।

आज का कार्टून

भाई-बहन की जोड़ी मोदी-ताकाइची ने रचा इतिहास

हिंद प्रशांत में संतुलन की नई धुरी बने भारत-जापान

> जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में दस ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है।

नीरज कुमार दुबे

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं।

हम आपको बता दें कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' बताते हुए भारत और जापान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, विशेषकर जापान के नारा प्रांत से भारत के ऐतिहासिक जुाव को रेखांकित किया। वहीं ताकाइची ने भी मोदी को अपना 'बड़े भाई' बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग रहा। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारतीय तथा जापानी संस्थानों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की सूक्ष्म तकनीकी क्षमता और भारत की साफ्टवेयर विशेषज्ञता का मेल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को नई दिशा देगा। यह सहयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है।

रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली 'यूनिकॉर्न' के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि दोनों देश क्वॉड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक बदलते सामरिक समीकरणों के बीच यह रक्षा सहयोग विशेष महत्व रखता है।

साथ ही भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, धातु और उर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की, जिसके तहत रुपये और येन में सीधे व्यापार की संभावना पर काम होगा। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी।

साथ ही जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में दस ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है।

साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की व्यापक उत्पादन क्षमता और जापान की गुणवत्ता आधारित तकनीक मिलकर विश्व को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। इसके साथ ही भारत जापान जैव गैस पहल के अंतर्गत भारत में एक हजार जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

देखा जाये तो यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। चीन की सैन्य सक्रियता, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारत और जापान को और करीब ला दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर उठते सवालों के बीच टोक्यो अब नई दिल्ली को अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में देख रहा है। भारत भी जापान को केवल निवेशक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक सहयोगी के रूप में देख रहा है।

हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंधों ने भी इस साझेदारी को मजबूती दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी की जापान यात्राओं से शुरू हुआ यह संबंध अब व्यापक सामरिक साझेदारी का रूप ले चुका है। वर्तमान वार्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत जापान संबंध एशिया की सबसे निर्णायक रणनीतिक धुरी बन सकते हैं।

देखा जाये तो भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन पर दिखाई देगा। लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग और सामरिक विश्वास पर आधारित यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक आपूर्ति संकट और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और जापान का साथ आना एशिया में एक नए रणनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकती है।

वीआईपी कल्चर और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते श्रद्धा के केन्द्र

> यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सभी मंदिरों की व्यवस्था ही खराब है। अनेक मंदिर प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्नदान और सामाजिक सेवा में उत्तम कार्य भी कर रहे हैं। लाखों लोगों को भोजन, चिकित्सा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए आलोचना का उद्देश्य मंदिरों को बदनाम करना नहीं है, बल्कि उनका मैनेजमेंट करने वालों को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है। समय की मांग है कि सभी बड़े मंदिरों में पारदर्शी प्रबंधन, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, वित्तीय जानकारी का इंटरनेट पर पारदर्शी होना, ठेकों और खरीद प्रक्रियाओं में खुलापन हो। इसके अलावा मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए प्रत्येक भक्त समान है।

कल्याणी चौधरी

भारत को आस्था और अध्यात्म का देश माना जाता है। मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि लोगों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र भी हैं। भक्तगण अपने साथ उम्मीद, विश्वास और आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं लेकिन आज के दौर में कई बड़े मंदिरों की व्यवस्थाओं के रूप बदलते दिख रहे हैं। जहां की पहचान कभी भक्ति हुआ करती थी; वहां अब वीआईपी दर्शन, टिकटों की कई श्रेणियां, ठेकेदारी, व्यावसायीकरण और प्रशासनिक अक्षमता चर्चा का विषय बन गए हैं। सवाल यह नहीं है कि मंदिरों में सुविधाएं क्यों बढ़ रही हैं, बल्कि यह है कि क्या इन सुविधाओं की आड़ में भ्रष्टाचार पनप रहा है? क्या प्रबंधन के नाम पर बनाई गई व्यवस्थाओं के तले श्रद्धालुओं की आस्था पिस रही है?

आज देश के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन भी एक तरह की श्रेणी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। एक ओर वह श्रद्धालु है जो घंटों लाइन में खड़ा रहता है, दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो विशेष शुल्क, प्रभाव या सिफारिश के आधार पर कुछ ही मिनटों में गर्भगृह तक पहुंच जाता है। भगवान के सामने सभी बराबर माने जाते हैं, लेकिन व्यवस्था में यह समानता खत्म होती नजर आती है, हालांकि आम तौर पर दिखाई नहीं देती। यह वीवीआईपी कल्चर केवल सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि धार्मिक समानता पर भी सवाल खड़ा करता है।

धार्मिक स्थलों के आसपास तेजी से बढ़ता व्यावसायीकरण भी चिंता का विषय है। कई स्थानों पर प्रसाद, फूल, पूजा सामग्री, पार्किंग, लॉकर और अन्य सेवाओं के नाम पर मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। श्रद्धालु जो शांति की तलाश में मंदिर पहुंचता है, उसे कई बार बिचौलिया, अवैध गाइड्स और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। आस्था का वातावरण अब कारोबारी केंद्र के तौर पर बदला हुआ नजर आता है।

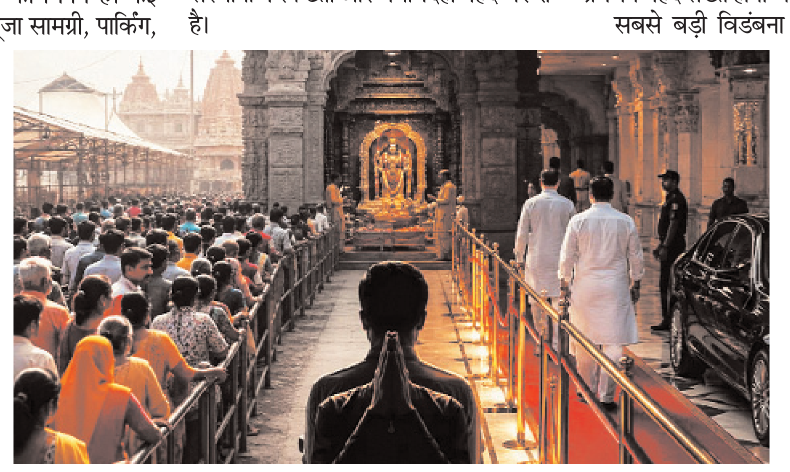

देश के बड़े मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी, माता वैष्णो देवी जैसे मन्दिरों और अन्य प्रमुख तीर्थों में समय-समय पर प्रबंधन, निर्माण कार्य, खरीद प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आते रहते है। इसका हालिया उदाहरण अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि मंदिर भी है। यह भी सच है कि हर आरोप सही साबित नहीं होता और कई मामलों में जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होती है। फिर भी बार-बार विवादों का सामने आना इस बात का संकेत है कि धार्मिक संस्थानों में स्पष्टता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान से जुड़ी कथित चोरी या घोटाले का मामला भी इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते भक्तों के बीच चर्चा का विषय बना है। श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ दान करते हैं, लेकिन जब उन्हीं दान पेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह जाती, बल्कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की निगरानी सवालों के घेरे में आ जाती है। यह उस जरूरत को जन्म देता है, कि मंदिरों की व्यवस्था और प्रबंधन बेहद सख्त होनी चाहिए।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्था के कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। कहीं लंबी कतारें हैं, कहीं विशेष टिकटों की अलग व्यवस्था और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग प्रवेश द्वार भी बने होते हैं। इससे आम आदमी के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी अब आर्थिक और सामाजिक हैसियत से तय होगा?

मंदिरों की व्यवस्था में तकनीक और आधुनिक प्रबंधन का उपयोग स्वागत योग्य है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य केवल पैसा बनाना रह जाए और श्रद्धालु का अनुभव बेहतर न हो, तो उसका महत्व कम हो जाता है। धार्मिक स्थल को किसी व्यावसायिक परिसर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भगवान के उस घर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वह सभी के लिए समानता का केंद्र हो, जहां वीवीआईपी या आम आदमी जैसा कुछ भी न हो।

हालांकि, यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सभी मंदिरों की व्यवस्था ही खराब है। अनेक मंदिर प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्नदान और सामाजिक सेवा में उत्तम कार्य भी कर रहे हैं। लाखों लोगों को भोजन, चिकित्सा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए आलोचना का उद्देश्य मंदिरों को बदनाम करना नहीं है, बल्कि उनका मैनेजमेंट करने वालों को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है।

समय की मांग है कि सभी बड़े मंदिरों में पारदर्शी प्रबंधन, नियमित स्वतंत्र ऑडिट, वित्तीय जानकारी का इंटरनेट पर पारदर्शी होना, ठेकों और खरीद प्रक्रियाओं में खुलापन हो। इसके अलावा मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए प्रत्येक भक्त समान है। जब मैनेंजमेंट ठीक होगा, तो भक्तों के लिए भगवान के दर्शन सहज होंगे, और ये उनके लिए मंदिर आने का सुखद अनुभव होगा; अन्यथा मंदिर के प्रशासन के प्रति लोगों की सोच लगातार नकारात्मक होती जाएगी।

भारत के खिलाफ वन डे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान

- कोल्स को पहली बार मौका, आर्चर, बटलर, जो रूट समेत 16 खिलाड़ी

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ इस महीने खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम में पहली बार अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को मौका मिला है। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और साकिब महमूद की वापसी हुई है। अनुभवी खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर और जो रूट भी भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे की सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा।

जेम्स कोल्स को पहली बार मिला मौका– 24 वर्षीय ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार इंग्लैंड की वनडे टीम में शामिल किया गया है। ससेक्स के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का उन्हें इनाम मिला है। वह बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इससे इंग्लैंड को टीम संयोजन में अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

जोश टंग भी वनडे डेब्यू के इंतजार में

तेज गेंदबाज जोश टंग को भी टीम में जगह मिली है। हालांकि वह अब तक इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ सीरीज में उन्हें अपना पहला ODI खेलने का मौका मिल सकता है।

एटकिंसन और साकिब महमूद की वापसी– इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और साकिब महमूद को भी टीम में बुलाया है। दोनों गेंदबाज चोट से उबरने के बाद फिर से चयनकर्ताओं का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं। इनके आने से इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी और मजबूत नजर आ रही है।

स्टार खिलाड़ियों से सजी इंग्लैंड की टीम– हैरी ब्रूक की अगुआई वाली टीम में कई अनुभवी और स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। जोफ्रा आर्चर अपनी रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे, जबकि पूर्व कप्तान जोस बटलर और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट मध्यक्रम को मजबूती देंगे। इसके अलावा जैकब बेथेल, बेन डकेट, विल जैक्स, सैम करन, आदिल रशीद और टॉम बैंटन जैसे खिलाड़ी भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं।

इंग्लैंड का वनडे स्क्वाड

हैरी ब्रूक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट, जोश टंग।

सीरीज का कार्यक्रम

पहला वनडे : 14 जुलाई, एजबेस्टन (बर्मिंघम)
दूसरा वनडे : 16 जुलाई, सोफिया गार्डंस (कार्डिफ)
तीसरा वनडे : 19 जुलाई, लॉर्ड्स (लंदन)

वैभव सूर्यवंशी की हर तरफ चर्चा

5 साल से डब्यू का इंतजार, घरेलू क्रिकेट में बना चुके 13 हजार से ज्यादा रन

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट में इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा विषय हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 साल के इस क्रिकेटर के इंटरनेशनल डेब्यू की हर तरफ से आवाज उठ रही है। मगर इसी बीच एक ऐसे खिलाड़ी का नाम भी भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में होगा जो पिछले पांच साल से अपने टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में चुने गए अभी एक महीना हुआ है लेकिन इस खिलाड़ी को 5 साल से इंतजार हैं।

हम बात कर रहे हैं घरेलू क्रिकेट में 13 हजार से ज्यादा कुल रन बना चुके अभिमन्यू ईश्वरन की। उन्हें 2021 में पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था। उसके बाद से लगातार कई सीरीज में वह टेस्ट टीम के स्क्वाड में चुने गए, मगर आज तक उनका डेब्यू नहीं हो पाया है। पिछले साल शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम में भी अभिमन्यू मौजूद थे, मगर इंटरनेशनल कैप का उन्हें अभी भी इंतजार है।

उलटफेर से बचा अर्जेंटीना

केप वर्डे के आत्मघाती गोल से अंतिम-16 में पहुंची मेसी की टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार (4 जून) को मियामी में केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना उलटफेर से बाल-बाल बच गया। केप वर्डे के डाइनी बोर्गेस ने आत्मघाती गोल किया, जिससे डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की राउंड ऑफ 16 यानी प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की हो गई। 5 लाख अबादी आइलैंड देश केप वर्डे ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन लियोनेल मेसी की टीम की किस्मत अच्छी रही की आत्मघाती गोल हुआ और केप वर्डे का सफर समाप्त हो गया। अर्जेंटीना अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए मिस्त्र का सामना होगा। इससे पहले मेसी ने 29वें मिनट में अपने करियर का रिकॉर्ड 20वां वर्ल्ड कप गोल करके मौजूदा चैंपियन को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। यह इस वर्ल्ड कप में मेसी का 7वां गोल था, जिससे वह गोल्डन बूट की रेस में किलियन एम्बाप्पे से आगे निकल गए। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में पिछले 8 मैचों में गोल किया है।

रोमेरो का 111वें मिनट में गोल

पहले हाफ तक अर्जेंटीना आगे रहा, लेकिन केप वर्डे के डेरॉय डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल था। 90 मिनट के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना के लिसेंड्रो मार्टिनेज ने 92वें मिनट में गोल किया। इसके कुछ ही समय बाद केप वर्डे के सिडनी लोपेस कैब्राल ने 103वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। केप वर्डे के डाइनी बोर्गेस ने 111वें मिनट में आत्मघाती गोल किया। इससे अर्जेंटीन 3-2 से मैच जीत दिलाकर आखिरी 16 में पहुंचा दिया।

मेसी फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने

सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड भी उनके नाम

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी ने शुक्रवार यानी 4 जुलाई को इतिहास रच दिया। वे फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। मियामी में केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना का मैच मेसी का 30वां फीफा वर्ल्ड कप मैच था। इस मैच में मेसी ने एक गोल किया और वो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। मेसी के अलावा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने 30 या उससे ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस सीजन में अब तक अपनी टीम के लिए कुल 7 गोल किए हैं और इंटरमिलान के लौटारो मार्टिनेज के साथ मिलकर तीन बार की चैंपियन टीम के अटैक की कमान संभाल रहे हैं। मेसी ने केप वर्डे के खिलाफ एक गोल किया और उन्होंने साल 2022 में अपने बनाए रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। मेसी ने उस सीजन में 7 गोल किए थे जबकि साल 2026 में भी उन्होंने अब तक कुल 7 गोल किए हैं। मेसी फीफा विश्व कप के दो सीजन में 7-7 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने।

आत्मघाती गोल के बाद भी मिस्र जीता

- 92 साल का इंतजार खत्म, सालाह के छलके आंसू

नई दिल्ली। होसाम अब्दुलमागुद के शूटआउट में निर्णायक गोल के दम पर पहली बार फीफा विश्व कप नॉकआउट मुकाबला खेलते हुए आत्मघाती गोल के बाद भी मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया जबकि निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर था। इसके साथ ही उसका 92 साल का इंतजार खत्म हो गया। वह पहली बार 1932 में विश्व कप खेला था और पहली बार राउंड ऑफ-16 में पहुंचा। जीत के बाद मिस्र ने चौथी बार विश्व कप खेलते हुए यह जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में तीन में से एक भी बार जीत नहीं सका है। अब मिस्र का सामना मंगलवार (7 जून) को गत चैम्पियन अर्जेंटीना से होगा जिसने केप वर्डे को अतिरिक्त समय में 3 .2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई है।

- **मांसपेशी की चोट के बावजूद सालाह खेले–** शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया के हैरी साउटार का निशाना चूका और 18 वर्ष के लुकास हेरिंगटन का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। मिस्र के लिये होसाम के अलावा महमूद साबिर, रामी राबिया और लिवरपूल के पूर्व स्टार मोहम्मद सालाह ने गोल दागे। मांसपेशी की चोट के बावजूद सालाह ने यह मैच खेला। आस्ट्रेलिया के लिये शूटआउट में जैकसन इरविन और अवेर माबिल ने गोल किये।

13 साल की भारतीय शतरंज खिलाड़ी

प्रतीती बोरदोलोई का कमाल

नई दिल्ली। साक्षी राज। 13 वर्षीय प्रतीती बोरदोलोई इटली के मोंटेसिल्वानो में आयोजित फिडे विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2026 में भारत की इकलौती पदक विजेता रहीं। बेंगलुरु की वुमन फिडे मास्टर (WFM) ने गर्ल्स अंडर-18 वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने 11 राउंड में 9 अंक बनाए और पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहीं। उन्होंने खुद से पांच साल बड़ी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलते हुए टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक दिया।

फिडे विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2026 में भारत छह वर्गों में 13 खिलाड़ियों के साथ उतरा था, लेकिन पदक सिर्फ प्रतीती ने जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपना पहला वुमन इंटरनेशनल मास्टर (WIM) नॉर्म भी हासिल किया और उनकी फिडे रेटिंग में 129 से ज्यादा एलो अंक जुड़े।

विश्व चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट का गैरी कास्पारोव से है खास कनेक्शन

गैरी कास्पारोव से खास संयोग

प्रतीती की कहानी को और खास बनाता है एक दिलचस्प संयोग। उनका जन्म गैरी कास्पारोव के जन्म के ठीक 50 साल बाद 13 अप्रैल 2013 को हुआ था। गैरी कास्पारोव का जन्म 13 अप्रैल 1963 को हुआ था। जहां यह जन्मदिन का संयोग अपने आप में रोचक है, वहीं उनके कोच ग्रैंडमास्टर प्रवीण थिप्से का मानना है कि समानता सिर्फ तारीख तक सीमित नहीं है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, प्रवीण थिप्से ने कहा,उनमें कुछ ऐसे गुण दिखते हैं। किसी टूर्नामेंट में खराब स्थिति में होने पर भी वह अच्छी योजना बनाती हैं ताकि वापसी करके शीर्ष पर पहुंच सकें। इटली में उनका यह जुझारूपन साफ नजर आया। 2129 की फिडे रेटिंग के साथ 16वीं वरीयता प्राप्त प्रतीती ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। उन्होंने सात जीत और चार ड्रॉ के साथ 11 राउंड में 9 अंक जुटाए।

सिर्फ शतरंज नहीं, गणित में भी कमाल– प्रवीण थिप्से के अनुसार, प्रतीती सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने बताया, प्रतीती पूरी तरह सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नहीं हैं। वह गणित की जादूगर हैं और सभी परीक्षाओं में प्रथम आती हैं। बेंगलुरु की रहने वाली प्रतीती ने इस साल अहमदाबाद में राष्ट्रीय अंडर-17 गर्ल्स चैंपियनशिप जीतकर विश्व युवा चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था।

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा

करणबीर बने नंबर 1- टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं रहे। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रिया के कप्तान व ओपनर बल्लेबाज करणवीर सिंह ने पीछे छोड़ दिया और वो इस मामले में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा अब दूसरे नंबर पर आ गए। करणवीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ 28 जून को खेले गए मैच में अपनी 164 रन की पारी के दौरान 12 छक्के लगाए और रोहित से आगे निकल गए।

करणवीर सिंह 205 छक्के लगा चुके

करणवीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 12 छक्के लगाए और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। करणवीर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने टी20आई में 159 मैचों में 205 छक्के लगाए थे। करणवीर सिंह ने टी20आई में अब तक खेले 60 मैचों की 59 पारियों में कुल 207 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में यूएई के मुहम्मद वसीम तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 99 मैचों में कुल 196 छक्के लगाए हैं।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने 113 मैचों में 179 छक्के लगाए हैं जबकि इंग्लैंड के ओपनर बैटर व विकेटकीपर जोस बटलर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 156 टी20आई मैचों में 175 छक्के अब तक लगाए हैं। इस लिस्ट में छठे स्थान पर मार्टिन गप्टिल मौजूद हैं जबकि ग्लेन मैक्सवेल 10वें स्थान पर मौजूद हैं। बाबर हयात इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं।

रोनाल्डो टॉप 10 में भी नहीं

एम्बाप्पे-मेसी के सबसे ज्यादा गोल

FIFA World Cup 2026 के गोल्डन बूट की रेस में शामिल शीर्ष 10 खिलाड़ी

नई दिल्ली। फुटबॉल का महासंग्राम फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और राउंड ऑफ 32 अपने आखिरी चरण में है। गुरुवार को स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहीं दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल में एंट्री की।

इस मुकाबले के बाद गोल्डन बूट की रेस में शामिल टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में भी बदलाव हुआ।

खास बात यह कि दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट के टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। जबकि किलियन एम्बाप्पे इसमें टॉप पर हैं। लियोनल मेसी के भी एम्बाप्पे के बराबर सबसे ज्यादा गोल हैं। मगर फ्रांस के स्टार फुटबॉलर के नाम दो असिस्ट भी हैं।

2026 के टॉप स्कोरर

रैंक	खिलाड़ी	देश	पोजिशन	गोल	असिस्ट	मिनट
1	किलियन एम्बाप्पे	फ्रांस	फॉरवर्ड (FW)	6	2	378
2	लियोनेल मेसी	अर्जेंटीना	फॉरवर्ड (FW)	6	0	223
3	एर्लिंग हालैंड	नॉर्वे	फॉरवर्ड (FW)	5	0	309
4	हैरी केन	इंग्लैंड	फॉरवर्ड (FW)	5	0	394
5	उस्मान डेम्बेले	फ्रांस	फॉरवर्ड (FW)	4	2	304

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए न्नाधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेल: alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670